सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 165, नई दिल्ली । रविवार, 25 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है, संतुलन बनाये रखने के लिए चलते रहना जरूरी है।

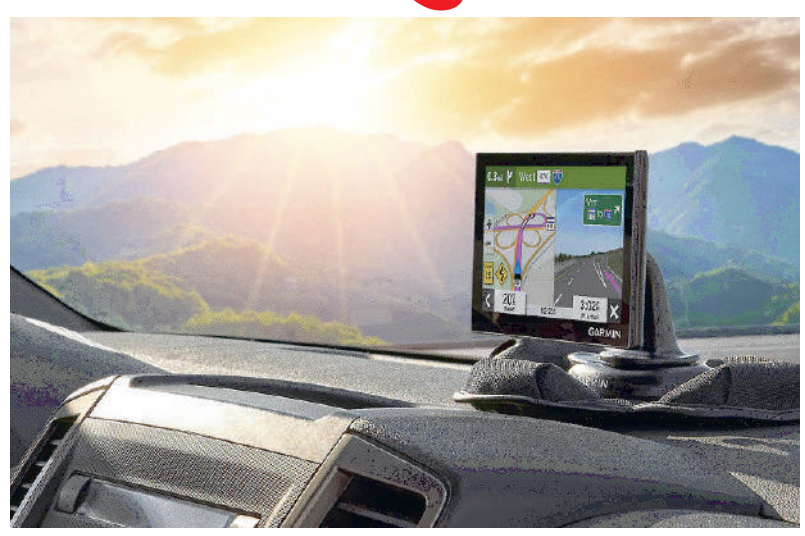

03 केजरीवाल के 'काम का जवाब काम' से देने में विफल भाजपा
06 जाति जनगणना की जरूरत क्यों?
08 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा

दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा वाहनों में क्या जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश **"दिल्ली के किसी भी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा कोई अन्य वाहन ना तो खरीदा जायेगा और ना ही किराए पर लिया जाएगा"** और स्वयं दिल्ली के सभी सरकारी विभागों के नोडल अधिकारी होने के बावजूद दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रवर्तन शाखा के लिए अनगिनत डीजल वाहन खरीदे और उन पर वीआईपी/ फैंसी नंबर जो आम जनता के लिए बोली प्रक्रिया में बड़ी क़ीमत अदा करने पर मिलता हैं लगा कर दिए। दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा का कार्य दिल्ली सीमा के अंदर ही है फिर भी डीजल वाहनों को खरीदना वह भी तब जब सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन उपल्ब्ध थे और दिल्ली में डीजल वाहनों का व्यावसायिक गतिविधियों में पंजीकरण बंद और डीजल वाहनों को आयु सीमा भी दिल्ली की सड़को पर चलने के लिए 10 साल। क्या बिना वजह/ बिना कारण सिर्फ अपनी हठ के लिए और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जनता का पैसा बर्बाद करना परिवहन विभाग द्वारा उचित था, बड़ा सवाल ? अब प्रश्न यह भी उठता है की यह वाहन किस उद्देश्य के लिए खरीदे गए थे और क्या इन वाहनों द्वारा वही उद्देश्य/ कार्य लिया जा रहा है या यह वाहन प्रवर्तन शाखा और अन्य परिवहन विभाग के अधिकारियों के निजी कार्य में प्रयोग किए जा रहे हैं। हमे प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग ने इन वाहनों में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी नही लगवाया जिससे कोई जांच एजेंसी यह ना जान सके की वाहन किस समय किस उद्देश्य की पूर्ति में स्लगन है और कहा है। **परिवहन विभाग प्रवर्तन शाखा के विशेष आयुक्त जनता को जवाब दे :-**

जब दिल्ली के प्रदुषण नियंत्रण के लिए आप के विभाग द्वारा लोगो के वाहन घर तक से उठवाए जाते रहे हैं तो अपनी शाखा जिनका कार्य सीएनजी/ इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों से पूरा हो सकता था और दिल्ली सरकार द्वारा आदेश भी जारी हो चुका था तो डीजल वाहन क्यों खरीदे गए ? और यह वाहन उदेशित कार्यों के लिए ही प्रयोग हो रहे की जांच के लिए इसमें जीपीएस नेविगेशन सिस्टम क्यों नहीं लगवाया गया ?

टॅम्पल्स ऑफ लिबरलाइज़ेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

जन्माष्टमी पर घर से निकलने से पहले पढ़ें यह खबर, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में यातायात व्यवस्था के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंदिर में प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार खुला रहेगा और आगंतुकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। मंदिर परिसर में अन्य सभी द्वार बंद रहेंगे और दो निकास द्वार होंगे। मंदिर मार्ग पर किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में यातायात व्यवस्था के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि मुख्य मंदिर में प्रवेश मंदिर मार्ग से होगा, जहां काली बाड़ी मार्ग या पेशवा रोड की तरफ से पहुंचा जा सकता है।

इसके अलावा हैंड बैग, ब्रीफकेस, पार्सल, खाने के पैकेट, कैमरा, मोबाइल फोन और अन्य बैटरी से चलने वाले उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले आगंतुकों को मंदिर के द्वार तक जाने वाले मेटल डिटेक्टर से गुजरने से पहले अपने जूते उतारने होंगे। मंदिर के अधिकारियों द्वारा काली बाड़ी मार्ग और पेशवा रोड पर हिंदू महासभा कार्यालय से सटे स्टाल में जूते जमा करने की व्यवस्था की गई है।

मंदिर में प्रवेश के अन्य सभी द्वार रहेंगे बंद

एडवाइजरी में कहा गया कि गीता भवन और वाटिका में प्रवेश मुख्य मंदिर द्वार से होगा। मंदिर परिसर में प्रवेश के अन्य सभी द्वार बंद रहेंगे। मंदिर परिसर से दो निकास द्वार हैं।

काली बाड़ी मार्ग पर आने वाले सभी लोग वाटिका गीता भवन की ओर जाने वाली निकास (वाटिका खुलने वाली) लेन से आगे बढ़ेंगे।

पेशवा रोड की ओर जाने वाले सभी लोगों को गीता भवन की ओर से बाहर निकलने के लिए गेट नंबर तीन का उपयोग करना होगा। गेट नंबर तीन से प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

काली बाड़ी मार्ग के पंचकुइयां रोड गोल चक्कर पर पार्क स्ट्रीट गोल चक्कर, उद्यान मार्ग और पेशवा रोड के बीच मंदिर मार्ग पर किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक सहायता बूथ बनाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी में सभी को जन्माष्टमी का सुरक्षित और खुशहाल उत्सव मनाने का आश्वासन दिया है।

चोरों ने रोकी दिल्ली मेट्रो की रफ्तार, केबल चोरी होने से रेड लाइन कॉरिडोर की ट्रेन सेवाएं रहीं बाधित

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर शनिवार सुबह से ही तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवा प्रभावित है। झिलमिल से मानसरोवर पार्क के बीच सिग्नल का केबल चोरी हो गया है जिससे सिग्नल काम नहीं कर रहा है। इस वजह से दिलशाद गार्डन से शहादरा तक 25 किलोमीटर की धीमी रफ्तार से मेट्रो चल रही है। डीएमआरसी ने सुबह ही इसकी सूचना दी।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कारिडोर रेड लाइन पर शनिवार को साढ़े पांच घंटे से मेट्रो का परिचालन प्रभावित है। इस वजह से यात्रियों को सफर में देरी का सामना करना पड़ा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि झिलमिल से मानसरोवर पार्क के बीच मेट्रो कॉरिडोर पर सिग्नल का केबल चोरी होने से सिग्नल काम नहीं कर रहा है। इस वजह से दिलशाद गार्डन से शहादरा तक 25 किलोमीटर की धीमी रफ्तार से मेट्रो चल रही है। परिचालन प्रभावित होने का कारण स्पष्ट नहीं किया है।

DMRC ने मेट्रो प्रभावित होने की दी जानकारी

स्थिति यह है कि दिलशाद गार्डन से शहादरा स्टेशन के बीच मेट्रो धीमी गति से चल रही है। डीएमआरसी ने सुबह 8.45 बजे ट्वीट कर रेड लाइन पर दिलशाद गार्डन से शाहदरा के बीच मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की सूचना दी।

रेड लाइन पर लगातार समस्या बनी हुई

इससे लगातार यह समस्या बनी हुई है लेकिन रेड लाइन पर शहीद स्थल से दिलशाद गार्डन और शहादरा से रिठाला के बीच मेट्रो का परिचालन सामान्य है। प्रभावित हिस्से रात में सिग्नल को ठीक किया जाएगा। इसलिए रेड लाइन सुबह मेट्रो का परिचालन सामान्य हो पाएगा।

जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन जाने वालों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से चलेगी स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा और वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने के साथ ही एक ईएमयू के यात्रा विस्तार करने का निर्णय लिया है। तिलक ब्रिज से मथुरा के बीच 04076/04075 विशेष ट्रेन चलेगी।

कहां-कहां होगा ठहराव ?

25 अगस्त व 26 अगस्त को 04076 नंबर की विशेष ट्रेन तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन से सुबह साढ़े नौ बजे रवाना होगी। दोपहर 12.15 बजे यह मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।

वापसी 04075 नंबर की विशेष ट्रेन मथुरा जंक्शन से अपराह्न साढ़े तीन बजे रवाना होगी और शाम छह बजे तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव हजरत निजामुद्दीन, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, कोशी कलां, छाता, वृंदावन रोड और भूतेश्वर में होगा।

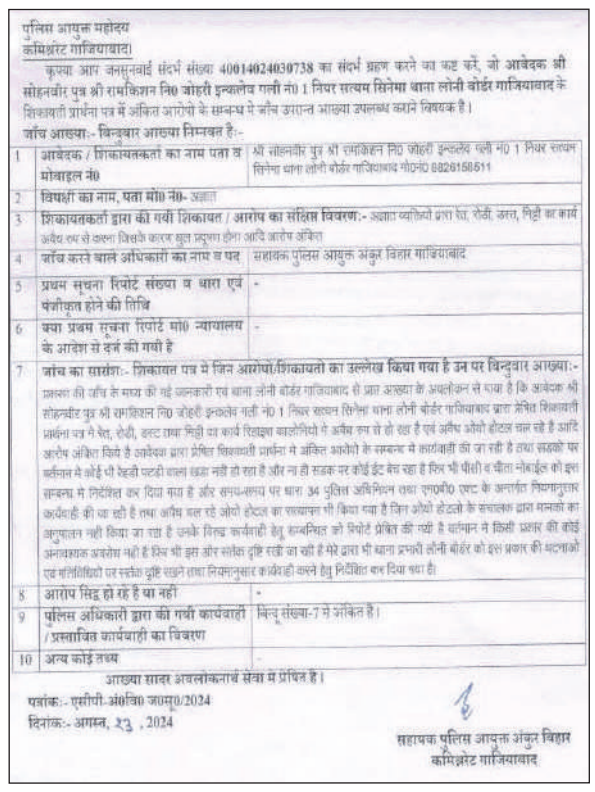

दिल्ली-रेवाड़ी के बीच तेज गति से चलेंगी ट्रेनें, रेलवे के इतिहास में पहली बार TRT के जरिए पूरा हुआ ट्रैक का काम

मुंबई और वैष्णो देवी के लिए रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, कई राज्यों के शहरों से होकर गुजरेंगी; जानिए रूट और टाइमिंग

मथुरा तक चलेगी गाजियाबाद-पलवल ईएमयू

गाजियाबाद से पलवल के बीच चलने वाली 04968/04407 नंबर की ईएमयू को रेलवे ने अस्थाई तौर पर मथुरा तक विस्तार देने का निर्णय लिया है। 25 अगस्त और 26 अगस्त को यह ट्रेन मथुरा जंक्शन तक चलेगी। 26 अगस्त व 27 अगस्त को यह मथुरा जंक्शन से गाजियाबाद के लिए रवाना होगी।

लोनी बोर्डर पर अवैध कारोबार, अतिक्रमण, पार्किंग व प्रदूषण चरम सीमा पर, लेकिन नही कोई सुनवाई

परिवहन विशेष न्यूज

लोनी, गाजियाबाद। उतर प्रदेश केजिला गाजियाबाद की तहसील लोनी मे लोनी बोर्डर पर अवैध कारोबार अवैध अतिक्रमण सडको पर ट्रेक्टर ट्राली की अवैध पार्किंग लोनी बोर्डर क्षेत्र प्रदुषण मे नम्बर एक लेकिन कोई कार्रवाई नही कोई सुनवाई नही माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनसुनवाई पोर्टल जनता-जनार्दन की शिकायत के लिए चलाया हैजिससे अधिकारी जनता-जनार्दन की शिकायत की सुनवाई ना करे जायज शिकायत पर कार्रवाई ना करे तो जनता जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते है लेकिन प्रशासन तो माननीय मुख्य मंत्री जी के जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नही कर रहा है केवल झुटा निस्तारण दिखाकर शिकायत बन्द कर देते है मुख्य मंत्री जी के बार बार सख्त कार्रवाई के निर्देश को भी नही मानते अपनी मनमर्जी से निस्तारण दिखाकर शिकायत बन्द कर देते हैजनता हार थक कर सरकार कोकोसती है सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कब्जा रिहाइश क्षेत्र मे प्रतिबन्धित रेत रोडी.डस्ट और मिट्टी का अवैध भंडारण व्यवसायिक कार्य के लिए प्रतिबन्धित ट्रेक्टर ट्राली हजारो की संख्या मे रात दिन बेलगाम दोड रहे है ज्यादातर पर प्रदुषण प्रमाण पत्र मान्य वाहन बीमा प्रमाण पत्र चालक लाइसेंस भी नही है जो क्षेत्र मे हर समय ध्वनी प्रदुषण डीजल चालित का प्रदुषण सडक पर रेत रोडी.डस्ट का प्रदुषण फैला रहे है लेकिन प्रशासन बिलकुल मोन है कोई कार्रवाई नही कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है प्रशासन सरकार को फैल करने मे लगा हुआ है कोई साफ-सफाई नही।

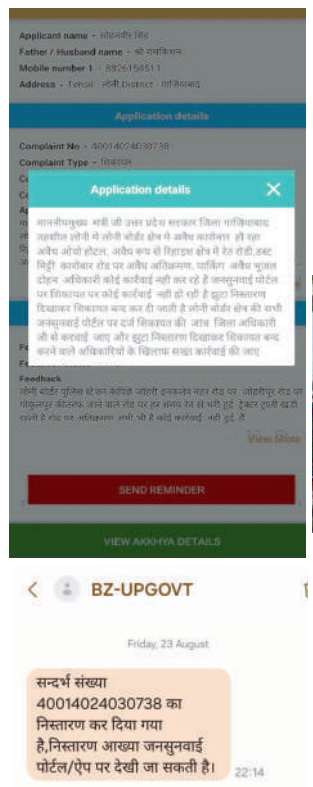

कई पुण्यों का फल देता है कृष्ण जन्माष्टमी व्रत

भगवान विष्णु ने संसार में धर्म की स्थापना व अधर्म के नाश हेतु अनेक अवतार लिए। इन्हीं में से एक अवतार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में लिया। श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि में हुआ था। अतः इस पावन तिथि को प्रत्येक वर्ष भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम व आस्था के साथ मनाया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रेरणा स्वरूप रहा है जो जीवन के अनेक सूत्रों को बताता है और यही अमूल्य सूत्र जीवन को दिशा और मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं..

जन्माष्टमी व्रत का महत्त्व

जन्माष्टमी के संदर्भ में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि इस व्रत को किस दिन मनाया जाए। जन्माष्टमी में अष्टमी को दो प्रकारों से व्यक्त किया गया है, जिसमें से प्रथम को जन्माष्टमी और अन्य को जयंती कहा जाता है। स्कंदपुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्रत होता है। यदि दिन या रात्रि में कलामात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। कृष्णपक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाना चाहिए तथा व्रत का पालन करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कृष्णपक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपद माह में हो तो इसे जयंती कहा जाएगा। वसिष्ठ संहिता के कथन के अनुसार अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में पूर्ण न भी हो तो मुहूर्त मात्र में भी अहोरात्र के योग में व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण के एक अन्य कथन के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत को करते हैं, उनके पास लक्ष्मी का वास होता है। विष्णु पुराण के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तो उसमें कृष्ण का अर्चन और पूजन करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है। भृगु संहिता के अनुसार जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि, ये पूर्वविद्धा ही करनी चाहिए तथा तिथि एवं नक्षत्र के अंत में पारणा करना चाहिए।

जन्माष्टमी की धूम

कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पावन अवसर पर मंदिरों को फूलों, बिजली की झालरों तथा रंग-बिरंगी झंडियों से आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर कई मंदिर समितियों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खुले मैदानों को विशेष पंडालों से सजाया जाता है जिनमें झांकियों और गीत-संगीत के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में कुछ दिनों पहले से ही कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर भजन संध्या आयोजित होती है तथा भगवान की लीलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। आम तौर पर तिथि और नक्षत्र को लेकर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव दो दिन मनाया जाता है जिसे उपासक अपने-अपने योग के अनुसार मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भारत के अतिरिक्त विश्व के कई अनेक हिस्सों में भी धूमधाम से मनाया जाता है।

मोहरात्रि

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि भी कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्रीकृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जगने से संसार की मोह-माया से मुक्ति प्राप्त होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव संपूर्ण विश्व को आनंद-मंगल का संदेश देता है। जन्माष्टमी के दिन कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस दिन दूध और दूध से बने व्यंजनों का सेवन किया जाता है। भगवान कृष्ण को दूध और मक्खन अति प्रिय था, अतः जन्माष्टमी के दिन खीर और पेड़े, माखन, मिस्री जैसे मीठे व्यंजन बनाए और खाए जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत मध्य रात्रि को श्रीकृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही पूर्ण होता है।

मटकी फोडऩे का दही-हांडी समारोह

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों व घरों को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इस त्योहार को कृष्णाष्टमी अथवा गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के दौरान भजन-कीर्तन गाए जाते हैं व नृत्य एवं रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ दही-हांडी जैसे आयोजन भी होते हैं, जिसमें मिट्टी के एक बर्तन में दही, मक्खन इत्यादि रख दिए जाते हैं। मटकी को काफी ऊंचाई पर लटका दिया जाता है जिसे फोडऩा होता है। इसे दही-हांडी आयोजन कहते हैं और जो भी इस मटकी को तोडक़र उसमें रखी सामग्री को प्राप्त कर लेता है, उसे ईनाम दिया जाता है।

विष्णु का महत्त्वपूर्ण अवतार

गीता की अवधारणा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि जब-जब धर्म का नाश होता है, तब-तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूं। अतः जब असुर एवं राक्षसी प्रवृत्तियों द्वारा पाप का आतंक व्याप्त होता है, तब-तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इन पापों का शमन करते हैं। भगवान विष्णु का इन समस्त अवतारों में से एक महत्त्वपूर्ण अवतार श्रीकृष्ण का रहा। भगवान स्वयं जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, उस पवित्र तिथि को लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं।

जन्माष्टमी व्रत, 26 अगस्त 2024, सोमवार

भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म माता देवकी व वासुदेव जी की आठवीं संतान के रूप में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि 12:00 बजे हुआ था।

इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त, सोमवार को मध्य रात्रि 2:00 बजे तक रहेगी। अतः अबकी बार जन्माष्टमी व्रत 26 अगस्त 2024, सोमवार को रखा जाएगा।

जन्माष्टमी मुहूर्त्त-:
26 अगस्त 2024, सोमवार,
निशीथ पूजा मुहूर्त-:
मध्य रात्रि 12:00 से 12:45 तक
अवधि-:
0 घंटे 44 मिनट

जन्माष्टमी विशेष-:

जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण, नाम जप, मंत्र जप इत्यादि किया जाता है। पूरे दिन व्रती व्रत रहने के बाद रात में 12 बजे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल के साथ सात्विक वस्तुओं का भोग लगाया जाता है उसके उपरांत व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं।

केशकाल घाटी - बस्तर का प्रवेश द्वार

कोंडागांव जिले में स्थित केशकाल घाटी बस्तर के प्रवेश द्वार के रूप में विख्यात है, जो छत्तीसगढ़ के शेष भाग को बस्तर से जोड़ती है.

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर यह घाटी कोंडागांव एवं कांकेर के मध्य स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं मनमोहक दृश्यों के कारण सभी को आकर्षित करती है.

अपनी सर्पाकार घुमावदार सड़कों के लिए प्रसिद्ध केशकाल घाटी की सुंदरता वर्षा ऋतु में विहंगम दृश्य प्रदान करती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.

सर्वप्रथम 1879 में इस घाटी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, जो 1890 में पूर्ण हुआ. इसके पश्चात वर्तमान काल तक इस घाटी का समय-समय पर पुनर्निर्माण होता रहा.

केशकाल घाटी में अवस्थित तेलीन सती माता पर क्षेत्रवासियों की अनन्य आस्था है, यही कारण है कि इस मार्ग से निकलने वाले सभी वाहन देवी को प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं.

जन्माष्टमी : हे कृष्ण आओगे न!

हे किशन-कन्हैया, सारे जग के तुम हो खिवइयां,
नाराज़ हूँ मैं तुमसे, कब तक ये बासुरी बजाओगे.
छलनी हो रहा तन-मन और तुम ऐसे गुनगुनाओगे.
इस कलयुग में द्रोपदियों को हैं, तुम्हारा इंतज़ार.
न जाने इस तरुणाई ने कौनसा ज़हर पी लिया हैं.
रुकंसर और रुकौरवोंर की ही तरह जन्म ले लिया हैं.
माँ के दूध से भी अब देखों इन्होंने मुँह फेर लिया हैं.
दुशासनों की फौज़ लिए, ये रसूखदार विचर रहें हैं.
हमारी बेटियों की अस्मतों को ये तार-तार और
माँ के आँचल में भी कोख को ज़ार-ज़ार कर हैं.
अरे, कान्हा कब पिघलोगे? क्या, चीखें सुन रहें हो?
क्या मेरी तपस्या के तुम, अभी-भी दिन गिन रहें हो!
याद रखों और ज्यादा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता.
माता देवकी और वासुदेव की राह नहीं तक सकता.
जन्माष्टमी पर सप्तमी और छब्बीस को सोमवार है,
हे कृष्ण, हे मुरलीधर, हे देवकी के नंदन आओगे न,
राह तकती द्रोपदियों के ज़ख्मों पे मरहम लगाओगे न.
इन दुशासनों को दण्डनायक बन बहुत तडपाओ न.

नंदोत्सव : ब्रज मंडल का प्रमुख उत्सव

नंदोत्सव भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के दूसरे दिन समूचे ब्रजमंडल में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है। ब्रज क्षेत्र के गोकुल और नंदगांव में श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के दूसरे दिन नंदोत्सव का विशेष आयोजन होता है। शास्त्रों के अनुसार कंस की नगरी मथुरा में अर्धरात्रि में श्रीकृष्ण के जन्म के बाद सभी सैनिकों को नींद आ जाती है और वसुदेव की बेडियां खुल जाती हैं। तब वसुदेव कृष्णलला को गोकुल में नंदराय के यहां छोड़ आते हैं। नंदराय जी के घर लला का जन्म हुआ है, धीरे-धीरे यह बात पूरे गोकुल में फैल जाती है। अतः श्रीकृष्ण जन्म के दूसरे दिन गोकुल में नंदोत्सव पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद मास की नवमी पर समस्त ब्रजमंडल में नंदोत्सव की धूम रहती है। इस दिन सुप्रसिद्ध लठ्ठे के मेले का आयोजन किया जाता है। मथुरा जिले में वृंदावन के विशाल श्री रंगनाथ मंदिर में ब्रज के नायक भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के दूसरे दिन नंदोत्सव की धूम रहती है।

उत्सव : अर्धरात्रि में श्रीकृष्ण का जन्म कंस के कारागार में होने के बाद उनके पिता वसुदेव कंस के भय से बालक को रात्रि में ही यमुना नदी पार कर नंद बाबा के यहां गोकुल में छोड़ आए थे। इसीलिए कृष्ण जन्म के दूसरे दिन गोकुल में नंदोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद नवमी के दिन समस्त ब्रजमंडल में नंदोत्सव की धूम रहती है।

दधिकांदो : यह उत्सव 'दधिकांदो' के रूप मनाया जाता है। दधिकांदो का अर्थ है दही की कीच। हल्दी मिश्रित दही फेंकने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। मंदिर के पुजारी नंद बाबा और जसोदा के वेष में भगवान कृष्ण को पालने में झुलाते हैं। मिठाई, फल, मेवा व मिश्री लुटाई जाती है। श्रद्धालु इस प्रसाद को पाकर अपने आपको धन्य मानते हैं।

रंगनाथजी मंदिर : वृंदावन में विशाल उत्तर भारत के श्री रंगनाथ मंदिर में ब्रज के नायक भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के दूसरे दिन नंदोत्सव की धूम रहती है। नंदोत्सव में सुप्रसिद्ध लठ्ठे के मेले का आयोजन किया जाता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जगह-जगह मनाई जाती है। उत्तर भारत के सबसे विशाल मंदिर में नंदोत्सव की निराली छटा देखने को मिलती है। दक्षिण भारतीय शैली में बने प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में नंदोत्सव के दिन श्रद्धालु लठ्ठे के मेले की एक झलक पाने को खड़े होकर देखते रहते हैं।

जब भगवान 'रंगनाथ' रथ पर विराजमान होकर मंदिर के पश्चिमी द्वार पर आते हैं तो लठ्ठे पर चढने वाले पहलवान भगवान रंगनाथ को दंडवत कर विजयश्री का आशीर्वाद लेते हैं और लठ्ठे पर चढऩा प्रारंभ करते हैं। 35 फुट ऊंचे लठ्ठे पर जब पहलवान चढऩा शुरू करते हैं, उसी समय मचान के ऊपर से कई मन तेल और पानी की धार अन्य ग्वाल-बाल लठ्ठे पर गिराते हैं जिससे पहलवान फिसलकर नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। इसको देखकर श्रद्धालुओं में रोमांच की अनुभूति होती है। भगवान का आशीर्वाद लेकर ग्वाल-बाल पहलवान पुनः एक दूसरे को सहारा देकर लठ्ठे पर चढने का प्रयास करते हैं।

थायराइड की है समस्या तो जरूर करें धनिया का सेवन

मिताली जैन

धनिया में क्वेरसेटिन और विटामिन सी जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप धनिया का सेवन करते हैं तो इससे थायराइड कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं, जिससे थायराइड फ़ंक्शन में सुधार हो सकता है।

धनिया का इस्तेमाल हम सभी अपनी किचन में जरूर करते हैं। कभी धनिया के बीज को खाना पकाते हुए शामिल करते हैं तो कभी हरा धनिया की मदद से अपने खाने को गार्निश करते हैं। धनिया में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और इसलिए जब इसे आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो इससे आपकी सेहत को लाभ मिलता है। हालांकि, अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो धनिया आपक लिए विशेष रूप से लाभदायी है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि थायराइड रोगियों के लिए धनिया किस प्रकार फायदेमंद साबित हो सकता है-

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

धनिया में क्वेरसेटिन और विटामिन सी जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप धनिया का सेवन करते हैं तो इससे थायराइड कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं, जिससे थायराइड फ़ंक्शन में सुधार हो सकता है।

होते हैं डिटॉक्सीफाइंग गुण

धनिया को अपने डिटॉक्सीफाइंग गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब आप धनिया का सेवन करते हैं तो इससे शरीर से मर्करी जैसे हैवी मेटल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। ये हैवी मेटल्स थायराइड फ़ंक्शन में बाधा डाल सकती हैं, इसलिए जब शरीर में इन मेटल्स की उपस्थिति कम होती है तो थायराइड हेल्थ इंप्रूव हो सकती है।

कोलेस्ट्रॉल को करे कंट्रोल

थायराइड को अक्सर बहुत सी बीमारियों से जोड़ा जाता है। कुछ मामलों में, थायराइड के कारण नई बीमारियां विकसित होने लगती हैं। थायराइड का मुख्य कारण कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि है। धनिया के बीज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे थायराइड हार्मोन को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है।

वजन को मैनेज करने में सहायक

धनिया मेटाबॉलिज्म और पाचन में सुधार करने में मददगार है, जिससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। यह हाइपोथायरायड रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। हाइपोथायरायड मरीजों को अक्सर बढ़ते वजन की शिकायत होती है, लेकिन धनिया की मदद से आप अपने वजन को बैलेंस कर सकते हैं।

संस्कारशाला: बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना - एक अनमोल अनुभव

डॉ. अंकुर शरण

बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। आज के समाज में, बुजुर्गों के प्रति हमारा जो रवैया है, उसे देखकर यह लेख लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। हम अपनी धरोहर को भूलते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य की कल्पना में आज से दूर होते जा रहे हैं।

हम में से बहुत से लोग या तो अतीत में जी रहे हैं या आने वाले युग की कल्पना कर रहे हैं। यदि हम आज को संवारना शुरू करें, तो निस्संदेह हमारा भविष्य भी उज्ज्वल होगा और बीता हुआ आज भी। इसी विचार के साथ, 'संस्कारशाला' के माध्यम से हम अपने बड़े-बुजुर्गों की कहानियाँ लेकर आपके सामने आते रहेंगे।

आचरण और विचार: मेरी नानी अम्मा की सीख

"आचरण" शब्द का हिंदी में अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, उसकी आदतें, और उसका नैतिक या सामाजिक आचरण ।

एक कहानी जो मेरी नानी अम्मा से सुनी, वह आचरण और विचार की है। उन्होंने बताया कि यदि आपके आचार-विचार सही हैं, तो आपको जीवन में किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। वह कहती थीं, "आचरण ठीक रखिए, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा।"

उन्होंने इस विचार को अचार बनाने से भी जोड़ा। नानी के अचार बनाने के दौरान की एक सीख मुझे आज भी याद है: जिस फल या सब्जी को काटने के बाद थोड़ी देर खुला छोड़ दिया जाए, वह सड़ जाती है। लेकिन सही मसालों और तेल के मिश्रण से वही सब्जी महीनों, सालों तक संरक्षित रहती है।

सोशल मीडिया और बदलती मानसिकता

आज के समय में, हम सब भी जैसे उसी फल-सब्जी की तरह हो गए हैं जो खुले विचारों के कारण जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें छोटी-छोटी बातें भी प्रभावित कर देती हैं। जब मैं अपने बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, तो महसूस करता हूं कि उनका जीवन कितना धैर्य और शांति से बिता।

हमारी जिंदगी अब इतनी तेज़ हो गई है कि हमें सबकुछ तुरन्त चाहिए। लेकिन प्रकृति के खिलाफ आप कभी नहीं चल सकते।

बुजुर्गों के साथ समय बिताने का महत्व

हमारे बुजुर्ग भले ही आधुनिक तकनीक से सीधे तौर पर जुड़े न हों, लेकिन उनके विचार और अनुभव अनमोल हैं। उनका सानिध्य, उनका साथ एक बड़ा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को जितना जल्दी समझेंगे, उतना बेहतर।

अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए। आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा, जो शायद ही आपको कहीं और मिल सके। मुझे अपनी नानी अम्मा से बात करके जितनी शांति और सुकून मिलता है, वह किसी और से बात करने में नहीं मिलता।

आज मेरी नानी की उम्र उतनी ही हो चली है जितना हमारे भारत को आजाद हुए समय हुआ है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उनका जन्मदिन मनाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे लिए एक अनमोल सौभाग्य है।

नानी की उम्र ने उन्हें अनुभवों और ज्ञान का भंडार बना दिया है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके साथ बिताया गया हर पल हमें उनके जीवन के अनमोल अनुभवों से रूबरू कराता है, और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो जाता है।

आज, जब हम उनकी उम्र और जीवन के अनुभवों को संजीदगी से देखते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हें खुशी के ऐसे पल दें जो वे हमेशा याद रख सकें। इस दिन को विशेष बनाने का सबसे बड़ा उपहार जो हम उन्हें दे सकते हैं, वह है हमारा समय।

आइए, हम सभी अपने नानी-दादी और बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनकी कहानियों को सुनें, उनके अनुभवों से सीखें, और उन्हें महसूस कराएं कि वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका आशीर्वाद और उनके साथ बिताया गया समय हमें जीवन की सही दिशा दिखाने में मदद करेगा।

बुजुर्गों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के कुछ सुझाव

बातचीत का महत्व: अपने बुजुर्गों से नियमित रूप से बातें करें। उनकी कहानियों और अनुभवों को ध्यान से सुनें। इससे न केवल आपको ज्ञान मिलेगा, बल्कि उन्हें भी यह महसूस होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं।

सामूहिक गतिविधियों में शामिल हों: पारिवारिक आयोजनों और त्योहारों में बुजुर्गों को शामिल करें। उनके साथ समय बिताने के लिए खास मौके बनाएं, जैसे शाम को उनके साथ बैठकर चाय पीना या टहलने जाना।

आभार व्यक्त करें: अपने बुजुर्गों के प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। उनकी देखभाल और मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद कहें।

उनकी जरूरतों का ख्याल रखें: बुजुर्गों की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखें, जैसे उनकी पसंद की चीजें लाना या उनकी सेहत का ख्याल रखना।

धैर्य और सहनशीलता रखें: बुजुर्गों के साथ बातचीत करते समय धैर्य और सहनशीलता का परिचय दें। उनकी बातों को समझने का प्रयास करें, भले ही वे कई बार पुरानी बातों को दोहराएं।

बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनसे सीखना न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। इस धरोहर को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है।

अखबारों और मीडिया में एफिडेविट देती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं

सुषमा रानी

नई दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखने के भाजपा की सीबीआई के षड्यंत्र का पूरे देश के सामने पर्दाफ़ाश हो गया है। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए कल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला।

उन्होंने साझा किया कि, जिस दिन अदालत में जाकर सीबीआई कहती है कि ज़मानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है इसलिए ज़मानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अख़बारों की एकतरफ़ा हैडलाइन बन सके।

उन्होंने कहा कि, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कितनी भी साज़िशें रच लो, जीत तो एक दिन सच्चाई और ईमानदारी की ही होगी। एजेंसियों भले ही राजनीतिक इशारे पर नाचती हों लेकिन संविधान और न्याय हमेशा सच के साथ है।

इस बारे में प्रेस-कॉन्फ्रेंस के ज़रिए साझा करते हुए वरिष्ठ आप नेता व दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने भी कहा कि, कोर्ट में कल सीबीआई ने जिस एफ़िडेविट को जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय माँगा आज वो एफ़िडेविट देश के हर अख़बार में छपा है। सीबीआई का एफ़िडेविट तैयार था लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिन तक जेल में रखने के लिए सीबीआई ने कल सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला।

उन्होंने कहा कि, सीबीआई अखबारों और मीडिया में एफिडेविट देती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं देती क्योंकि उन्हें साज़िशन अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना है लेकिन भाजपा कितने भी षड्यंत्र कर ले, जीत आखिकार सच्चाई की ही होगी; अरविंद केजरीवाल जल्द दिल्लीवालों के बीच आयेंगे और CBI-ED के माध्यम से रचा जा रहा भाजपा का हर षड्यंत्र फेल होगा। आतिशी ने कहा कि, इसका सीधा मतलब है कि एफ़िडेविट तैयार था। सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया कि एफ़िडेविट तैयार नहीं है। यानी सीबीआई सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिन तक जेल में रखने के लिए ये साज़िश कर रही है।

सतेंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की रफ़्तार नहीं रुकी तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भी झूठे मुक़दमे में गिरफ़्तार कर लिया। आतिशी ने कहा कि, 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से पीएमएलए/ईडी के मामले में बेल मिलती है। उस ऑर्डर के अपलोड होने से पहले ही 21 जून की सुबह ईडी हाई-कोर्ट पहुँच जाती है और ऑर्डर आए बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवा देती है।

सदर बाजार में मेट्रो कार्य से हो रही दिक्कतों को लेकर फेस्टा ने अधिकारियों को अवगत करवाया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। सदर बाजार में मेट्रो का कार्य चल रहा है। कुछ व्यापारियों को दिक्कत भी आ रही हैं इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव, महासचिव राजेंद्र शर्मा, कमल कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल सहित अनेक व्यापारियों ने मेट्रो अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नितिन सिंह राजपूत, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर स्वर्णेंदु मैती की फेडरेशन के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें मेट्रो कार्य से हो रही कुछ समस्याओं अवगत करवाया।

परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने मेट्रो अधिकारियों को बताया कि उनकी क्रेन दिन में आने से काफी जाम लग जाता है जो मिठाई पुल से कुतुब रोड आना हो या कुतुब रोड से मिठाई पुल जाना हो घंटो जाम की स्थिति बन जाती है। एक तो वैसे ही सिंगल रोड है और दूसरा क्रेन हटाने के बात भी काफी व्यापारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा अगर यही क्रेन रात को या सुबह-सुबह दुकानों खुलने से पहले आ जाए इस मुश्किलों से हमें छुटकारा मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर किसी कारण वर्ष रोड को बंद करना पड़ता है तो इसकी सूचना व्यापारियों को पहले पहले से दिन और समय बताएं। इस समय से इस समय तक रोड यह बंद रहेगी और अपने गाड्र्स को चौक पर खड़ा करके ट्रैफिक को दूसरी ओर से निकलने का कार्य करें।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा राकेश यादव, राजेंद्र शर्मा व कमल कुमार ने मेट्रो अधिकारियों को कहां कि वह गॉड्स की संख्या बढ़ने, मेट्रो के जो बोर्ड लगे हैं उनके साथ में जो पटरी वाले बैठ जाते हैं उसके कारण रोड में आने जाने वालों को काफी दिक्कत होती है। उनको हटाने के लिए अपने गॉड्स लगाए जिस पर रोड खुली हो सके।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व के राकेश यादव ने बताया कि मेट्रो और फेस्टा का एक जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें कोई भी दिक्कत होगी, उसको आपस में शेयर किया जाएगा।

इस पर मेट्रो अधिकारी नितिन सिंह राजपूत ने सारी समस्या सुनने के बाद फेडरेशन को आश्वासन दिया हम यही कोशिश करेंगे कि दिन में क्रेन ना आए दूसरा में जल्द ही गार्डों को बढ़ाएंगे साथ ही जो मेट्रो बोर्ड के साथ पटरी लग रही है। इसके लिए फेडरेशन भी नगर निगम को पत्र लिखे और हम भी लिखते हैं। गार्ड को सख्त हिदायत दी जाएगी के यहां पर कोई पटरी ना लग सके।

मुर्दाघर को भी नहीं बख्शा, बनाया अय्याशी का अड्डा

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

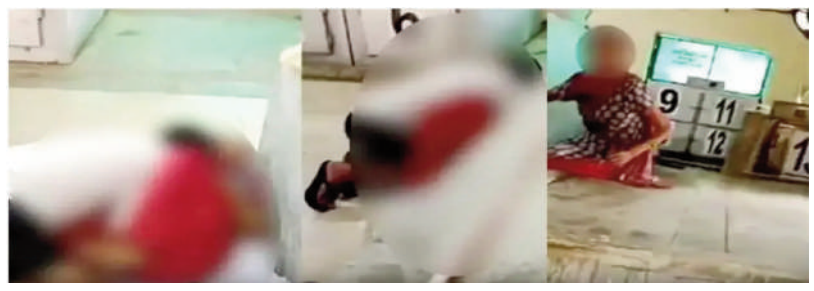

जिंदो के साथ लाशो के बीच पोस्टमार्टम हाउस में धड्डले से चल रहा था अय्याशी का अड्डा। एक तरफ अभी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर कोलकाता समेत पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने हडकंप मचा दिया है। दरअसल नोएडा के एक पोस्टमार्टम हाउस के वायरल वीडियो ने सभी लोगो के कान खडे कर दिए है। यहां के कर्मचारियों ने बेखौफ मुर्दाघर की लाशों के बीच अय्याशी का अड्डा बना रखा था। मुर्दो के बीच अय्याशी का सच उधेडते सामने आए वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हडकंप मच गया है। कुछ ही सेकेंड में यह अश्लील वीडियो इंटर्नेट पर आग की तरह फैल गया। ऐसी औछी और हैरान कर देने वाली हरकत को देखकर एक्शन में आए प्रशासन ने इस मामले में 3 आरोपियो को हिरासत में ले लिया है। वहीं 2 मुख्य आरोपियो को नौकरी से हाथ धोना पडा है। बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस का पूरा सच अभी भी सामने नही आया है। इसको लेकर अब नए खुलासे हो रहे है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो घटना का वीडियो शुक्रवार 23 अगस्त को सामने आया था। जबकि 12 अगस्त, 2024 को यह वीडियो बनाया गया था। घटना भी उसी दिन की है। सबसे हैरानी की बात है यहां के स्वास्थ्य अधिकारी को पहले से इसकी जानकारी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 12 अगस्त को पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रिजर हॉल में 12 शव रखे थे। इस दौरान वहां के कर्मचारी ने महिला के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया। जबकि दूसरे कर्मचारी ने वीडियो बनाया वो डीप फ्रिजर हॉल के बाहर पहरा दे रहा था। पोस्टमार्टम हाउस के अधिकारियो को अगले दिन इस वीडियो की जानकारी हो गई थी। लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नही की। आखिर क्यों नहीं तत्पर कार्रवाई नहीं की गई? घटना के 10 दिन बाद यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियो पर एक्शन लिया। बता दे कि वीडियो में मौजूद शख्स उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है। शख्स का नाम शेर सिंह है। जो पोस्टमार्टम हाउस में संविदा पर कार्यरत है। बता दें कि वीडियो शुक्रवार 23 अगस्त को सामने आया है। जबकि 12 अगस्त को बनाया गया था। घटना भी उसी दिन की थी। हैरानी की बात है कि स्वास्थ्य अधिकारी की नाक के नीचे यह अश्लील अड्डा पता नहीं कब से चल रहा था। उल्लेखनीय है कि शेर सिंह एक महिला के साथ पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रिजर हॉल में आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। तभी परवेंदर सिह नामक दूसरे कर्मचारी ने शेर सिंह को चद्दर लाकर दी। इस दौरान प्रवेंदर सिंह मोबाइल में वीडियो बनाने लगा। महिला ने उसे वीडियो बनाने से मना किया। लेकिन वो नहीं माना। बता दें कि वीडियो बनाने वाला मोबाइल एंबुलेंस चालक भानू प्रताप कमरे के बाहर खडा था। और उसने अपने फोन को परवेंदर को वीडियो बनाने के लिए दिया था। यूपी पुलिस मामले पर एक्शन लेते हुए शेर सिंह, परवेंदर और भानू प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि वीडियो में मौजूद महिला अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वही स्वास्थ्य विभाग ने परवेंदर सिंह, और शेर सिंह को नौकरी से निकाल दिया है।

महिलाओं के साथ दुष्कर्म के खिलाफ शांतिपूर्ण निकाला कैंडल मार्च

सुषमा रानी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली पूर्व निगम प्रत्याशी दीपक सूद ने देश में जगह-जगह महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के खिलाफ अपनी और कई संस्थानों की तरफ से आवाज उठाई। देश में निरंतर हो रहे हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म के खिलाफ त्रिलोकपुरी क्षेत्र में सामाजिक संगठनों के साथ सम्मिलित होकर शांतिपूर्ण विशाल #केंडल_मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में आरोपियों को फांसी की सजा मिले हम न्यायालय से अपील करते हैं। ताकि भविष्य में कोई भी किसी महिला या बहन बेटी को बुरी नजरों से ना देखें।

डीडीए की जमीन पर माफियाओं का कब्जा, कहीं चल रहा है सट्टा तो कहीं बन गई अवैध पार्किंग

राजधानी दिल्ली में क्या डीडीए अपनी जमीन की नहीं कर पा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। कहीं पर अवैध निर्माण बना हुआ है तो कहीं पर पार्किंग चल रही है। कहीं पर कबाड़ी वालों ने कब्जा किया हुआ है। कड़कड़डूमा गांव में दबंगों ने डीडीए की जमीन घेरी हुई है।

पूर्वी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर जमीन डीडीए के पास है। यमुनापार में डीडीए की जमीनों पर माफिया कब्जा कर राज कर रहे हैं। डीडीए की किसी जमीन पर दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम सट्टा चल रहा है तो कहीं पर लोग झुग्गी बसाकर रह रहे हैं। अवैध पार्किंग, ई-रिक्शा चार्जिंग, दूध की डेरियां चल रही हैं।

कई वरिष्ठ अधिकारियों ने साधी चुप्पी

आरोप है कि कब्जा व अतिक्रमण करवाने में डीडीए (DDA News) के अधिकारी खुद शामिल है, अतिक्रमण की एवेज में मोटी रकम वसूल रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों से इसपर जवाब मांगा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और नाम छापने से मना किया।

यह कहा कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ड्रोन सर्वे में लापरवाही के आरोप में भूमि प्रबंधन आयुक्त विक्रम सिंह को हटाकर उनके मूल कैडर भेज दिया है। ऐसे में उनका डीडीए के किसी मामले पर बोलना ठीक नहीं है। इतना कहा कि डीडीए समय-समय पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता है।

सरकारी जमीन पर खेला जाता है सट्टा

मंडावली में सद्भावना अपार्टमेंट के सामने डीडीए की जमीन है। यहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर झुग्गी है। यहां धड़ल्ले से सट्टा खेला जाता है। मोहल्ले के अधिकतर लोगों को यह बात मालूम है। सवाल उठाया कि क्या जिस विभाग की जमीन है उसको ही नहीं पता होगा कि उसकी जमीन पर क्या हो रहा है।

मंडावली थाने की कार्यशैली पर भी सवाल

उठाए कि पुलिस को भी सबकुछ पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। यह मामला एसडीएम के नेतृत्व में बनी एसटीएफ की बैठक में भी कभी नहीं उठा, क्या विभाग तभी कार्रवाई करेंगे जब लोग शिकायतें लेकर उनके कार्यालयों के चक्कर काटेंगे।

कड़कड़डूमा गांव में भी दबंगों ने डीडीए की घेरी जमीन

रिहायशी क्षेत्रों में डेरी चलाने पर प्रतिबंध है। लेकिन दल्लूपुरा गांव, न्यू उस्मानपुर, खिचड़ीपुर समेत अन्य क्षेत्र में डीडीए की भूमि पर ही डेरियां चल रही हैं। मंडावली और गाजीपुर में कबाड़ियों ने कब्जा किया हुआ है।

कड़कड़ी मोड स्थित कैलाश अस्पताल के पीछे भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले ने कब्जा किया हुआ है। कड़कड़डूमा गांव में भी दबंगों ने डीडीए की जमीन घेरी हुई है। यहां लोग रहने के साथ ई-रिक्शा चार्जिंग, पार्किंग चला रहे हैं। गौतमपुरी, हर्ष विहार में भी डीडीए की जमीन को लोगों ने घेर रखा है।

हिंदू पर्व समारोह समिति सदर बाजार दिल्ली द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हिंदू पर्व समारोह समिति सदर बाजार दिल्ली (पंजी) द्वारा 23 अप्रैल 2024 को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर लाइब्रेरी रोड रामलाल असली मार्ग आजाद मार्केट दिल्ली 6 से शुरू हुई। जगह-जगह पर लोगों ने मंच लगाकर इस शोभायात्रा का अभिनंदन किया। हारे का सहारा हेल्पिंग हैंड्स (एनजीओ) द्वारा पहाड़ी धीरज, सदर बाजार में अभिनंदन स्टेज लगाया गया। शोभा यात्रा का अभिनंदन हर का सहारे (हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ) के संरक्षक धर्मेंद्र कुमार जैन एवं संस्थापक अध्यक्ष कार्तिक जैन, सहित कार्यकारिणी सदस्य आनंद शर्मा, अंश शर्मा, सतीश कुमार एवं दिलीप कुमार और भी कहीं सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे।

केजरीवाल के 'काम का जवाब काम' से देने में विफल भाजपा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 24 अगस्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी भाजपा और उसकी केंद्र सरकार को पांच माह से रूकी बुजुर्गों की पेंशन जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा ने 5 माह से बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली 2500 रुपए की पेंशन रोक रखी थी और वो दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। शनिवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दुर्गेश पाठक ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराने के पीछे भाजपा का एकमात्र मकसद दिल्ली का काम रोककर लोगों को परेशान करना है। केजरीवाल को जेल भेजने के बाद भाजपा ने सबसे पहले बुजुर्गों पर हमला किया और उनकी पेंशन रोक दी। आज पूरे देश में दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है और इससे भाजपा और उसकी सल्तनत घबरा गई है। इसीलिए उसने फर्जी केस बनाकर ''आप'' के सारे नेताओं को जेल भेजने की साजिश रची। अगर भाजपा सोच रही है कि वो केजरीवाल को जेल में डाल कर दिल्ली का विकास रोक देगी तो गलतफहमी में है।

दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा, उसकी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की साजिश अब धीरे-धीरे सबके सामने आ रही है और लोगों को सब समझ में आने लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में गिरफ्तार करने के पीछे भाजपा का मकसद केवल दिल्ली के हर नागरिक को परेशान करना था। उसने दिल्ली में सीवर की सफाई रोक कर, पानी का कनेक्शन काट कर, लोगों के पैसे बंद कर, केंद्र सरकार का फंड रोक कर हर तरह से दिल्लीवालों को परेशान करने की कोशिश की। 2015 में जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, पिछले 8 सालों से हर तरफ केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है। हर जगह लोग कहते हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली-पानी मुफ्त दे रही है, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा की सुविधा दे रही है, दिल्ली में आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे में रहता है। कोई घाटा नहीं है, कोई लोन नहीं लिया गया है।

दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सरकारी अस्पतालों को ठीक किया और मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की, लेकिन भाजपा ने उन्हें रोकने के लिए जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया, उन्हें भी गिरफ्तार करवा दिया गया। संजय सिंह संसद में भाजपा से सवाल पूछते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबके बावजूद इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची ताकि पूरा दिल्ली मॉडल ध्वस्त हो जाए। पिछले एक-डेढ़ साल से भाजपा दिल्ली को नर्क बनाने पर तुली हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल में जो काम किए, भाजपा की पूरी कोशिश थी कि सीएम को जेल में डालकर दिल्ली के सारे काम रोक दिए जाएं और दिल्लीवासियों को परेशान किया जाए।

उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को यह गलतफहमी है कि वे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली का विकास रोक लेंगे, तो वे गलत हैं। केजरीवाल जल्द ही बाहर आएंगे और उन्होंने 8 सालों में जो शानदार विकास किया है, उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के सपने को पूरा करेंगे। लोग दिल्ली पर गर्व करेंगे। इससे पूरे देश में विकास की चिंगारी जलेगी और हर व्यक्ति अपने राज्य में कहेगा कि हमें भी केजरीवाल सरकार की तरह स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आएंगे और फिर से दिल्ली का विकास शुरू होगा। भाजपा को अपनी गंदी राजनीति अब बंद कर देनी चाहिए। दिल्लीवासियों ने उन्हें मौका देकर देख लिया है। 15 साल तक एमसीडी में रहते हुए उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया था। अब जब लोकतंत्र में जनता ने एक पार्टी को मौका दिया है, तो उसे काम करने देना चाहिए।

सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे से बढ़ी लोगों की परेशानी, कई इलाकों में लगा जाम

परिवहन विशेष न्यूज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद दौरे के दौरान कई इलाकों में जाम लग गया। सीएम करीब साढ़े तीन घंटे तक शहर में रहे और इस दौरान यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर आवाजाही रोक दी। अंबेडकर रोड पुराना बस अड्डा चौराहा हापुड़ रोड और राजनगर एक्सटेंशन में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इन दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को हिंदी भवन और रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर में करीब साढ़े तीन घंटे तक रहे। इन दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

मुख्यमंत्री की फ्लीट निकलने के दौरान यातायात रोका गया था। इस वजह से कई मार्ग पर वाहन चालकों को जाम में फंसना पड़ा। अंबेडकर रोड, पुराना बस अड्डा चौराहा, हापुड़ रोड और राजनगर एक्सटेंशन में इस दौरान वाहनों की कतार लग गयी।

शुक्रवार दोपहर करीब सवा 12 बजे यातायात पुलिस ने बस अड्डा चौराहा, अंबेडकर रोड, हापुड़ रोड, हापुड़ चुंगी चौराहा और राजनगर एक्सटेंशन मुख्य मार्ग पर यातायात रोक दिया। नवयुग मार्केट से चंद्रपुरी जाने वाले मार्ग को भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया था।

करीब पौने 12 बजे हिंदी भवन पहुंचा मुख्यमंत्री का काफिला

करीब दोपहर पौने 12 बजे मुख्यमंत्री का काफिला हिंदी भवन पहुंचा। उसके बाद वाहनों को निकलने दिया गया। इससे करीब आधा घंटे तक इन मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लोग परेशान रहे।

दोपहर करीब सवा दो बजे मुख्यमंत्री के हिंदी भवन से बाहर निकलने से पहले यातायात फिर बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। हालांकि इस दौरान भी वाहन चालकों को आधा घंटे तक जाम में फंसना पड़ा।

जलभराव के बीच निकली मुख्यमंत्री की फ्लीट

हापुड़ रोड पर दीनागढ़ी के सामने शुक्रवार दोपहर वर्षा के बाद जलभराव हो गया था। मुख्यमंत्री का काफिला हिंदी भवन जाने के लिए दीनागढ़ी के सामने से जलभराव के बीच ही गुजरा। सिहानी गेट थाने के सामने भी जलभराव से वाहन चालकों को परेशानी हुई। इस दौरान पैदल लोगों को भी रोक दिया गया।

पुलिस ने दुकानों को बंद कराया

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए हिंदी भवन के पास दीनागढ़ी में दोपहिया सेल-परचेज की दुकानों को पुलिस ने शुक्रवार दोपहर तक बंद करा दिया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद कुछ दुकानें खुलीं।

वीवीआइपी मूवमेंट के कारण यातायात कुछ स्थानों पर थोड़ी देर के लिए रोका गया था। सीएम की फ्लीट गुजरने के बाद यातायात सामान्य हो गया। -पीयूष कुमार सिंह, एडीसीपी ट्रैफिक

कम्प्यूटर टीचर पर महिला शिक्षक को मतांतरण कराने का लगा आरोप, पति की शिकायत के बाद केस दर्ज

गाजियाबाद जिले से मतांतरण का मामला सामने आया है। जहां पर एक कम्प्यूटर टीचर पर महिला टीचर ने आरोप लगाया है कि उसने उसका मतांतरण करने की कोशिश की है। पीड़िता के पति की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला को अपने साथ गुजरात भी ले गया था। फिलहाल मामल में जांच जारी है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के एक स्कूल की महिला शिक्षक के मतांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। महिला के पति ने एक कम्प्यूटर टीचर पर आरोप लगाते हुए कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोप है कि महिला को आरोपित गुजरात भी अपने साथ ले गया था। महिला के पहनावे, बातचीत और नमाज पढ़ता देखने पर स्वजन को शक हुआ था। कविनगर थानाक्षेत्र निवासी पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी एक स्कूल में पढ़ाती थीं।

आरोपित ने महिला को लिया अपने झांसे में

उनके ही स्कूल में फैजल नामक कम्प्यूटर शिक्षक के आने के बाद बातचीत बढ़ी। आरोपित ने महिला को अपने प्रभाव में ले लिया और बीते वर्ष 20 नवंबर से इस वर्ष 28 जनवरी तक अपने साथ गुजरात ले गया। गुजरात के राजकोट में महिला की नौकरी भी लगवाई गई। उसके बाद महिला वापस आ गई।

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

वापस आने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आ गया और दिनचर्या भी बदल गई। महिला अपने स्वजन से भी बात नहीं करती है। अब स्वजन का आरोप है कि उन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। महिला को घर से निकालने के लिए कहा जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस (Ghaziabad Police) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिसवाले ने 'दृश्यम' देखकर लिया आइडिया और रेलवे ठेकेदार का कर दिया मर्डर, केस सॉल्व करने में चकरा गई यूपी पुलिस

ग्रेटर नोएडा में फिल्मी स्टाइल में रेलवे ठेकेदार कत्ल कर दिया गया। इस घटना को दिल्ली पुलिस के निलंबित सिपाही ने अंजाम दिया है। हत्या से पहले उसने दृश्यम फिल्म देखकर प्लान बनाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने और खुद को बचाने के लिए ठेकेदार के फोन से खुद मैसेज किए। केस सॉल्व करने में नोएडा पुलिस का दिमाग भी चकरा गया।

ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के अल्फा दो सेक्टर के रहने वाले ठेकेदार अंकुश शर्मा की हत्या दिल्ली पुलिस के निलंबित सिपाही प्रवीण ने हथौड़ा मारकर की थी। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए हत्यारोपित की निशानदेही पर शुक्रवार को एलजी गोलचक्कर के समीप टी सीरीज की जमीन से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

'दृश्यम' फिल्म देखकर बनाया प्लान

ठेकेदार और हत्यारोपित के बीच प्रॉपर्टी की रकम के लेनदेन का विवाद था। हत्यारोपित ने वारदात को अंजाम देने से पहले 'दृश्यम' फिल्म देखी थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए वारदात से एक सप्ताह पहले इलाके में सुनसान जगहों की रेकी भी की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त क्रेटा कार व हथौड़ा बरामद किया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ठेकेदार को हत्यारोपित 13 दिन पहले रकम देने के लिए अपने साथ लेकर गया था और उसी दिन हत्या की कर दी थी। प्रवीण मेरठ के मोहल्ला मार्क पुरिया कस्बा बहसूमा का है। फिलहाल एसकेए सोसायटी के ट्यूविल टावर के फ्लैट संख्या 2126 में रह रहा था। इसी फ्लैट को लेकर लेनदेन का विवाद था।

फ्लैट हड़पना चाहता था हत्यारोपित

अंकुश शर्मा रेलवे में ठेकेदारी के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनका एसकेए सोसायटी में फ्लैट था। जिसे वह बेचना चाहते थे। ब्रोकर संचित ने फ्लैट बिक्री के लिए बीस फरवरी को प्रवीण का अंकुश शर्मा से परिचय कराया था। दोनों के बीच 1.18 करोड़ में डील हुई थी। दो किस्तों में रकम देना तय हुआ था। प्रवीण ने एडवांस में अंकुश के खाते में आठ लाख रुपये ट्रांसफर किए थे।

एग्रीमेंट के बाद 10 मई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से टीएम (ट्रांसफर मेमोरंडम) प्राप्त हो गया। आरोपित ने अंकुश को झांसे में लेकर फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। पहली किस्त 38 लाख रुपये देना तय हुआ था, लेकिन प्रवीण ने समय पर पैसे नहीं दिए। इसी बीच अंकुश कनाडा चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने संपत्ति खरीद फरोख्त की एक वेबसाइट पर फ्लैट को बेचने के लिए जानकारी अपलोड कर दी। जहां उसकी कीमत 1.60 करोड़ रुपये निर्धारित की गई।

'दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी', बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बोले सीएम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के कौशांबी स्थित रेडिसन होटल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। साथ बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हुई हिंसा को लेकर कहा कि भारत को अपने मित्र और शत्रु की पहचान करनी होगी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा।

साहिबाबाद। भारत को शत्रु और मित्रों की पहचान करनी पड़ेगी। गलती से भी शत्रु को मित्र न मान लें और मित्र को शत्रु न बना लें। अगर मित्र और शत्रु को पहचानने की ताकत होगी तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। भारतवासियों के बीच में ही फूट डालने की कोशिश हो रही है।

तमाम ऐसे तत्व जिनका ठिकाना कहीं और है। वे भारत में वह अलग-अलग स्थान पर अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको लेकर सचेत रहना होगा। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के संबंध में कौशांबी स्थित रेडिसन होटल में एक निजी कार्यक्रम के दौरान कहीं।

यूपी में कानून व्यवस्था एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा-CM

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। राह चलती बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता। क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने छेड़ा तो उसका परिणाम क्या होगा? 66 हजार हेक्टेयर भूमि माफिया के कब्जे से खाली कराई है।

15-20 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे। उनके गुर्गों ने जमीन कब्जा रखी थी। माफिया के यूपी में अलग-अलग ब्रांड बने हुए थे। वे सब बुलडोजर से घबराते हैं। पूर्व की सरकारी भूमि को खाली करने के लिए तो कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। माफिया बुलडोजर से डर रहे हैं।

यूपी सरकार जल्द ला रही एक फैमिली आईडी की योजना-यूपी सीएम

कॉमन मैन को डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन मैन के लिए तो वह सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज को स्वीकार करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में कोई व्यक्ति एवं अव्यवस्था अराजकता फैलता है तो उसके विषय में भी सोचना पड़ेगा।

उनकी सरकार जल्दी एक फैमिली आईडी की योजना ला रही है। इससे सरकारी किसी भी योजना से परिवार के सदस्य जुड़े होने का पता चलेगा। परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार के साथ जोड़ेंगे। हर व्यक्ति के हाथ में काम, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी को सम्मान होगा।

योगी के लिए दुनिया एक असीमित संसार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी के लिए पूरी दुनिया एक असीमित संसार है। कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। जब उनकी पार्टी ने उन्हें दायित्व सौंपा था तो सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के प्रति धारणा को बदलना। यूपी को वह भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित करेंगे।

उन्होंने बिना रुके व बिना हटे कार्य करते रहे। आज उसका परिणाम देख रहे हैं। सात वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के लोग जब कहीं जाते थे तो उनको गलत दृष्टि से देखते थे, लेकिन आप उनको भी सम्मान मिलता है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग धार्मिक यात्री आए हैं।

अलग-अलग फलों और फसलों के क्लस्टर्स बना रही योगी सरकार

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक टी. दामोदरन के अनुसार संस्थान, सरकार की मदद से लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशहरी और चौसा आम के लिए क्लस्टर बनाकर करीब 4000 बागवानों को जोड़ चुका है।

क्लस्टर में खेती की संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार पहले से विकसित कलस्टर्स की सुविधाएं बढ़ा रही है। साथ ही नए फलों और फसलों के क्लस्टर्स भी विकसित कर रही है। फल और फसल विशेष के इन क्लस्टर्स से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जहां बल्क (बड़ी मात्रा) में किसी चीज का उत्पादन होता है, वहां खरीदार खुद पहुंचने लगते। खरीदारों में प्रतियोगिता होने से उत्पाद की गुणवत्ता के अनुसार उसका वाजिब दाम भी मिलता है। खेतीबाड़ी भी बाजार के इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है।

बल्क में फलों या फसलों के उत्पादन का मतलब है, बड़े पैमाने पर बड़े रकबे में किसी एक फल या फसल की खेती। इसे उस फल या फसल का क्लस्टर भी कह सकते हैं। धीरे-धीरे वह कलस्टर उस फल या फसल की पहचान बन जाती है। जैसे-जैसे यह पहचान मुकम्मल होती जाती है, वैसे वैसे उस क्लस्टर के उत्पाद की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। मसलन मलीहाबादी दशहरी, सहारनपुर का चौंसा, बनारस का लंगड़ा, गोरखपुर और बस्ती का गवरजीत, अयोध्या, गोंठा और सहारनपुर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला, सिद्धार्थनगर का कालानमक धान और कुशीनगर का केला आदि।

ओडीओपी ने भी बढ़ा दी कलस्टर की संभावना

जिन जिलों के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) खेतीबाड़ी से संबंधित हैं उनको इस योजना के जरिये कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) देकर ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक की सुविधा देना इसी प्रयास का हिस्सा है।

आम के कलस्टर से लाभान्वित हो रहे 4000 किसान

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक टी. दामोदरन के अनुसार संस्थान, सरकार की मदद से लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशहरी और चौसा आम के लिए क्लस्टर बनाकर करीब 4000 बागवानों को जोड़ चुका है। इनको पुराने बागों के पुरोद्धार, बौर और फसल संरक्षा के उपाय, फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले तरीकों के बाबत जानकारी दी जाती है। इसका इन किसानों को लाभ भी हो रहा है। पहली बार मलिहाबाद से 5 टन दशहरी आम संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया।

योगी सरकार और विश्व बैंक से संचलित यूपी एग्रीस योजना में भी क्लस्टर का जिक्र

हाल ही में योगी सरकार और विश्व बैंक के बीच उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटर प्राइजेज स्ट्रेंथिंग (यूपी एग्रीस) नामक जिस योजना पर काम की सहमति बनी है उसमें भी एग्रो क्लस्टर्स बनाने का जिक्र है। इस पूरी योजना पर सरकार और विश्व बैंक मिलकर छह साल में 4000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। केंद्र सरकार भी क्लस्टर की संभावनाओं का किसानों के हित में अधिकतम लाभ लेना चाहती है।

केंद्र सरकार 1800 करोड़ रुपये की लागत से बनाएगी बागवानी के 100 क्लस्टर

हाल ही में केंद्रीय कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि अगले पांच वर्षों में केंद्र सरकार 1800 करोड़ रुपये की लागत से बागवानी के निर्यात केंद्रित 100 कलस्टर बनाएगी। सरकार की सब्जी उत्पादन के लिए भी क्लस्टर बनाने की तैयारी है।

केंद्र की इन योजनाओं का भी सर्वाधिक लाभ यूपी को होगा

स्वाभाविक है कि 9 तरह की वैविध्यपूर्ण जलवायु, इंडो गंगेटिक बेल्ट की सबसे उर्वर भूमि, भरपूर पानी और प्रचुर मात्रा में श्रम के रूप में मानव संसाधन और बाजार होने के नाते केंद्र की इन योजनाओं का उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लाभ भी मिलेगा।

सरकार भी योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों की दिलाने को तैयार

योगी सरकार ने केंद्र की मदद से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदेश के किसानों को दिलाने की तैयारी भी कर दी है। मसलन, प्रयागराज से हल्दिया तक देश के इकलौते जलमार्ग से सस्ते में कृषि उत्पादों का परिवहन होने भी लगा है। योगी सरकार की मंशा इस जलमार्ग का विस्तार अयोध्या तक करने की है। इससे प्रदेश के अवध और पूर्वांचल के बहुतेरे किसानों को लाभ मिलेगा। इसी तरह का लाभ मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से भी होगा।

अयोध्या में 36 हजार से अधिक रोजगार के अवसर लेकर आईं 48 कंपनियां

बता दें कि प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान के तहत हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। बीते साढ़े सात साल में साढ़े छह लाख से अधिक सरकारी और दो करोड़ से अधिक युवाओं को निजी सेक्टर में नौकरियों के अवसर प्राप्त हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को उनके गृह जनपद में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेशभर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रामनगरी अयोध्या में जहां एक तरफ विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है, साथ ही यहां के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियां रोजगार देने में भी अच्छी खासी रुचि दिखा रही हैं। 18 अगस्त को अयोध्या आयोजित रोजगार मेले में 36 हजार से अधिक जॉब्स ऑफर लेकर 48 से अधिक कंपनियां शामिल हुईं।

अयोध्या में स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार के अवसर लेकर आने वाली कंपनियों में अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन और आईटी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। रोजगार मेले में 10 हजार से अधिक युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं अबतक इनमें से साढ़े पांच हजार से अधिक युवाओं को प्लेसमेंट का ऑफर भी मिल चुका है। अयोध्या में रोजगार के अवसर लेकर आने वाली कंपनियों में इंस्टाह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी, टंबल ड्राई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, करियर ब्रिज, रीचा आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3415 से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। सरकार का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का है, ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। जनपदों में रोजगार मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय तथा एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है।

बता दें कि प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान के तहत हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। बीते साढ़े सात साल में साढ़े छह लाख से अधिक सरकारी और दो करोड़ से अधिक युवाओं को निजी सेक्टर में नौकरियों के अवसर प्राप्त हो चुके हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेलों में शामिल होकर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। दो दिन पहले ही में अंबेडकर नगर में भी सीएम योगी ने 6 हजार 7 सौ से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। इसके साथ ही 13 हजार से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट देकर टेक्नोलॉजी के जरिए सशक्त किया गया।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

रायपुर के 10 पार्किंग क्षेत्रों में लगेंगे फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

रायपुर के 10 पार्किंग क्षेत्रों में फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन टाटा और एथर पॉवर कंपनी की सहभागिता से लगाए जाएंगे। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने कार्यपालन अभियंता इमरान खान के साथ प्रस्तावित फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थल का निरीक्षण किया। यहां पीपीपी मोड पर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की सहभागिता से फास्ट ईव्ही चार्जिंग स्टेशन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है।

अभी रायपुर के 4 स्थानों, नगर निगम मुख्यालय भवन पार्किंग स्थल, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाठागांव, कलेक्टोरेट के सामने मल्टीलेवल पार्किंग, जयस्तंभ चौक के समीप पुराना बस स्टैंड मल्टीलेवल पार्किंग में फास्ट 4 व्हीलर ईवी चार्जिंग स्टेशन का संचालन किया जा रहा है।

काइनेटिक ग्रीन 18 महीने में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की बना रही योजना

परिवहन विशेष न्यूज

काइनेटिक ग्रीन पूरी तरह से तैयार है और एक आक्रामक उत्पाद को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इस साल की शुरुआत में ई-लूना के लॉन्च के बाद, अब इसकी नज़र इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस पर है। कंपनी ने पहले ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित करना शुरू कर दिया है और इसे 18 महीनों में लॉन्च करने का लक्ष्य है। यह ओला, बजाज के इलेक्ट्रिक चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसी गाड़ियों का सीधा प्रतियोगी होगा। इतना ही नहीं। काइनेटिक ग्रीन एक इलेक्ट्रिक L5 पैसेंजर थ्री-व्हीलर और गोल्फ कार भी पेश करने की योजना बना रही है, जिसे लेम्बोर्गिनी के सहयोग से डिज़ाइन किया गया है और यह एक साल से भी कम समय में बाज़ार में आने वाली है।

हाल ही में एक सफल फंड जुटाने के दौर के बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए काइनेटिक ग्रीन की सीईओ और सह-संस्थापक, सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने काइनेटिक ग्रीन के भविष्य के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, "हम जुटाए गए फंड का इस्तेमाल विनिर्माण, ईवी आरएंडडी और उत्पाद विकास और आक्रामक मार्केटिंग और ब्रांड निवेश के लिए करेंगे। हम एंकर-उत्पाद, ई-लूना को आम लोगों तक ले जाने और ग्राहकों को आईसीई से ईवी में बदलाव के लिए मनाने के उद्देश्य से इसे आक्रामक तरीके से मार्केटिंग करने पर विचार कर रहे हैं। यह सिर्फ़ हमारे उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे देश में जन जागरूकता पैदा करने के बारे में है।"

सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी के अनुसार ई-लूना की बिक्री बी2सी सेगमेंट और गिग वर्कर्स के बीच बढ़ी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-लूना चुनिंदा शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और वे अगले 12 महीनों में लगभग 350-400 डीलरों के मौजूदा स्तर से लगभग 800 डीलरों तक विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए B2C के लिए बड़े पैमाने पर विस्तार और बी2बी के लिए एक समर्पित सेटअप की योजना बनाई जा रही है। 100,000 लूना बेचना हमारा सपना है, लेकिन अगले 12 महीनों में 75,000 लूना बेचने का लक्ष्य होगा।

काइनेटिक ग्रीन की प्रमुख सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्पेस के लिए काइनेटिक ग्रीन की योजनाएँ सिर्फ़ ई-लूना तक सीमित नहीं हैं। वे एक पारिवारिक स्कूटर पर भी काम कर रहे हैं और ₹वाहन को बाज़ार में लाने में लगभग 18 महीने लगने की उम्मीद है।₹ उन्होंने बताया कि ₹हमारा उद्देश्य हमारे ई-स्कूटर को मौजूदा आईसी इंजन स्कूटरों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बनाना है। ग्राहकों को समान प्रदर्शन, अंडर-सीट स्टोरेज, रेंज मिलनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि 80 से 100 किमी की रेंज की दैनिक आवश्यकता पूरी हो। मुझे लगता है कि जब तक उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करता है, तब तक कीमत लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।₹ यह 100% भारत में निर्मित होगा और इसकी कीमत 1 लाख रुपये के करीब होगी।₹ उन्होंने संकेत दिया कि यह ओला, इलेक्ट्रिक चेतक और टीवीएस आईक्यूब को सीधी टक्कर देगा।

काइनेटिक ग्रीन के लिए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बाजार एक और प्रमुख फोकस क्षेत्र है। कार्गो के लिए एल5 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के सफल लॉन्च के बाद, लक्ष्य एल5 यात्री वाहन हैं। मोटवानी ने विस्तार से बताया कि एल5 हाई-स्पीड ऑटो हैं जो घर-घर की यात्रा के लिए अधिक उपयोगी हैं और दक्षिण और पश्चिम और बड़े शहरों में अधिक लोकप्रिय हैं। शुरुआत में संघर्ष हुआ और बिक्री में तेजी आने में समय लगा क्योंकि सीएनजी ईंधन बहुत सस्ता है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बैटरी की कीमतों में गिरावट के साथ, यह सेगमेंट भी गति पकड़ेगा, ₹हम अपना ईवी उत्पाद पोर्टफोलियो बना रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोकस यह भी है कि हम इस साल एल5 यात्री वाहन भी लॉन्च कर रहे हैं। ग्राहकों को लगभग 120-150 किमी की रेंज और हाई स्पीड चाहिए। बैटरी की कीमतें गिर रही हैं, एल3 पैसेंजर कैरियर भी काफी आकर्षक होते जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हम विकसित करेंगे।"

काइनेटिक ग्रीन गोल्फ कार्ट के लिए बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उत्सुक है। मोटवानी ने कहा कि गोल्फ कार्ट लेम्बोर्गिनी कनेक्शन को देखते हुए एक अभिनव आकांक्षापूर्ण पेशकश होगी और इसे वैश्विक फोकस के साथ बाजार में लाया जाएगा। इस फंडरेज़ के साथ, हम गोल्फ कार्ट को बाजार में लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगले 12 महीनों में हम मध्य पूर्व से पूरे गोल्फ कार्ट व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक नई पहल शुरू करेंगे। हम मध्य पूर्व से पूरे विनिर्माण के साथ-साथ वैश्विक व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह यूरोप के करीब है और अमेरिका के भी अपेक्षाकृत करीब है। अगले 6 से 9 महीनों में कुछ घोषणा की उम्मीद है, उन्होंने आशावादी नोट पर निष्कर्ष निकाला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे व्यवसाय इनक्यूबेशन से विनिर्माण चरण में आगे बढ़ रहा है और इसका वैश्विक दृष्टिकोण भी होगा।

ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी में भारी गिरावट, निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह

परिवहन विशेष न्यूज

अरबपति कारोबारी भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में इसकी हिस्सेदारी तेजी से घट रही है। यह कंपनी हाल ही में आईपीओ लेकर आई थी, जिसमें लिस्टिंग के बाद करीब 100 फीसदी का उछाल देखने को मिला। विश्लेषकों ने निवेशकों को ओला इलेक्ट्रिक के 'अस्थिर' स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी है।

प्रतिष्ठित ब्रोकरेज जेफरीज के अनुसार टीवीएस और बजाज ने अधिक किफायती इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इससे उनकी बाजार हिस्सेदारी में क्रमशः 4 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में टीवीएस की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत और बजाज की 18 प्रतिशत है।

ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो महीने-दर-महीने आधार पर जून तिमाही में इसकी बाजार हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 33 प्रतिशत हो गई।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक का मौजूदा वैल्यूएशन आकर्षक लग सकता है। लेकिन, निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर, ओला इलेक्ट्रिक के लगातार घाटे और इसके शेयर में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए।

विशेषज्ञ नए निवेशकों को ओला के शेयर मूल्य में स्थिरता का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट साजी जॉन ने कहा, ₹नए निवेशकों को अधिक स्थिर प्रवेश बिंदु का इंतजार करना चाहिए। वे उच्च जोखिम-इनाम अनुपात के साथ लंबी अवधि के लिए ओला इलेक्ट्रिक पर दांव लगा सकते हैं।₹

ओला इलेक्ट्रिक की शेयर बाजार में 76 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। इसके बाद इसमें तेजी आई और यह 158 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन, वहां से गिरावट शुरू हो गई और शुक्रवार को यह 126.26 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 20 फीसदी नीचे कारोबार कर रहे हैं। हाल ही में अपनी कारोबारी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने अलग-अलग कैटेगरी में मोटरसाइकिल भी लॉन्च की थी।

नए कार ड्राइवर 7 तरीकों से रखें अपने व्हीकल का ख्याल, लम्बे समय तक रहेगी चमचमाती

परिवहन विशेष न्यूज

हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि नया कार ड्राइवर हो या फिर पुराना सभी को किस तरह से अपनी कार का ख्याल रखना चाहिए। वहीं यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप कार की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी बेहतर बनी रहती है। इस सभी को फॉलों करने पर आपको बार-बार मैकेनिक के पास अपनी कार को नहीं ले जाना पड़ेगा।

नई दिल्ली। वो दिन चले गए जब कार सिर्फ अमीर लोगों के लिए हुआ करती थी और इसे खरीदना एक बड़ी बात होती थी। अब इसे खरीदना और चलाना सीखना बहुत आसान हो गया है। कई लोग इसे खरीद तो ले लेते हैं, लेकिन इसका सही से रखरखाव नहीं रख पता है। जिससे नई होने के बावजूद वह पुरानी दिखने लगती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप अपनी कार का रखरखाव किस तरह से करें कि वह हमेशा चमचमाती रहे।

कार के मैनुअल को सही से पढ़ें

बहुत से लोग होते हैं, जो कार के मैनुअल को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैनुअल को ध्यान से और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। इससे आपको अपनी कार के लिए जरूरी कुछ बुनियादी रखरखाव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। कार के मैनुअल में किसी भी समस्या के लिए अपने वाहन का निरीक्षण करने के तरीके के बारे में कई चीजों के बारे में पता चलता है। इससे आप कार से संबंधित समस्याओं को आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपनी कार के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और आपको इस पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।

कार लाइट इंडिकेटर के बारे में जानें

हाल में आने वाली अधिकांश कर सेंसर और वॉर्निंग सिस्टम से लैस होती है, जो कुछ भी गड़बड़ होने पर आपको सूचित करती हैं। इसलिए आपको यह समझना जरूरी हो जाता है कि अलग-अलग रंग की लाइट का क्या मतलब है। आमतौर पर आपने यह देखा होगा कि जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो आपको डैशबोर्ड पर कई लाइट थोड़ी देर के लिए जलती हैं। इस प्रक्रिया को बल्ब चेक कहा जाता है। अगर कोई खाल लाइट नहीं जल रही है, तो आपको मैनुअली इसे चेक करना चाहिए।

टायरों का नियमित करें चेक

आपको अपनी कार के टायरों को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। इस दौरान आपको देखना चाहिए कि इसके ट्रेड घिसे हुए न हों। इसके साथ ही यह भी चेक करे कि एक्स्ट्रा टायर और उससे संबंधित सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हों और कार में अपनी-अपनी स्थिति में हों।

इंजन ऑयल से लेकर गियरबॉक्स ऑयल तक करें चेक

आपकी कार की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखने के लिए इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले ऑयल का अहम रोल होता है। इसमें सबसे जरूरी इंजन ऑयल होता है जो इंजन में फ्रिक्शन को कम करता है। इसके फिल्टर को समय-समय पर साफ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको कार में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडिएटर कूलेंट, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड, विंडस्क्रीन वॉशर फ्लूइड, गियरबॉक्स ऑयल, क्लच फ्लूइड और डिफरेंशियल फ्लूइड की भी नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।

बैटरी चेक करें

बैटरी को साफ, टाइट और जंग-मुक्त कनेक्शन के लिए आपको इसकी नियमित रूप से चांज करनी चाहिए। अगर इस पर जंग लग गई है तो उसे आप बेकिंग सोडा और पानी के पेस्ट से साफ कर सकते हैं।

ब्रेक हमेशा रखें सही

सभी को कार के ब्रेक के महत्व के बारे में पता है। आप इन्हें गाड़ी चलाते समय आसानी से चेक कर सकते हैं। धीरे से ब्रेक लगाने पर आपको महसूस हो कि वे ढीले हैं या तुरंत काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आप मैकेनिक से जल्द से जल्द ठीक करवा लें। किसी भी कार चालक को चाहे वो नया ड्राइवर हो या पुराना सभी को कार से संबंधित बुनियादी चीजों के बारे में जरूर जानना चाहिए। जिसमें तेल बदलना, फ्लैट टायर बदलना, स्पार्क प्लग बदलना, कार की बैटरी बदलना, पेंट से खरोंच हटाना, वाइपर, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, एयर फ़िल्टर और ब्रेक पैड बदलना शामिल है।

हीरो मोटर्स ला रही 900 करोड़ का आईपीओ

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटर्स कंपनी समूह की ऑटो कंपोनेंट कंपनी हीरो मोटर्स लिमिटेड ने शनिवार, 24 अगस्त को सेबी के पास बाजार के लिए मसौदा पेशकश पत्र जमा कर दिया। कंपनी की योजना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए 900 करोड़ रुपये जुटाने की है।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के मुताबिक, आईपीओ के तहत 500 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर 400 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) करेंगे। ओएफएस में ओपी मुंजाल होल्डिंग्स 250 करोड़ रुपये और भाग्योदय इंवेस्टमेंट्स और हीरो साइकिल्स 75-75 करोड़ रुपये के शेयर पेश कर रही हैं। कंपनी आईपीओ से पहले 100 करोड़ रुपये जुटा सकती है और ऐसा होने पर नए आईपीओ का आकार छोटा हो जाएगा।

नए आईपीओ से जुटाए गए 202 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी 124 करोड़ रुपये से गौतम बुद्ध नगर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरण खरीदेगी।

हीरो मोटर्स भारत की अग्रणी ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, भारत और आसियान क्षेत्र में ऑटोमोटिव ओईएम को अत्यधिक इंजीनियर्ड पावरट्रेन समाधान प्रदाता के डिजाइन, विकास, निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। कंपनी दोपहिया वाहनों, ई-बाइक, ऑफ-रोड वाहनों, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों और भारी-भरकम वाहनों सहित विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन बनाती है। हीरो मोटर्स दो खंडों में काम करती है - पावरट्रेन समाधान और मिश्र धातु और धातु। भारत, यूनाइटेड किंगडम और थाईलैंड में इसके 6 प्लांट हैं। हीरो मोटर्स ने वित्त वर्ष 24 में 1064 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।

छात्रों ने बनाया देश का पहला ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश के उभरते इंजीनियरिंग छात्रों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में नई क्रांति ला सकता है। इस तकनीक के ज़रिए अब ईवी वाहनों को स्टेशन पर पहुँचने के बाद बिना सॉकेट और चार्जर के चार्ज किया जा सकेगा। इस क्रांतिकारी तकनीक ने न केवल ईवी की चार्जिंग प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया है, बल्कि यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को सुरक्षित करने में भी मददगार साबित हो सकती है।

इस नए आविष्कार में वायरलेस चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचते ही सक्रिय हो जाती है। इसमें चुंबकीय अनुनाद तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो वाहन और चार्जिंग स्टेशन के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के विद्युत प्रवाह संचारित करती है। यह तकनीक वाहनों में पहले से लगे एक छोटे रिसीवर के माध्यम से काम करती है, जो चार्जिंग प्लेटफॉर्म से ऊर्जा प्राप्त करता है और इसे बैटरी में स्थानांतरित करता है।

इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद के प्रतिष्ठित हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के पांच छात्रों की टीम ने तैयार किया है। टीम का नेतृत्व करने वाले छात्र सौरभ चौधरी ने बताया, ₹हमारी कोशिश ईवी चार्जिंग को इतना सरल और आसान बनाना था कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में झिझकें नहीं।" उनकी प्रेरणा दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम करना है। उनका मानना है कि अगर इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए तो पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है।

इस तकनीक से न केवल चार्जिंग का समय कम होगा, बल्कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की लागत भी कम होगी क्योंकि इसके लिए महंगे चार्जिंग उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, यह सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे मौजूदा ईवी वाहनों में भी आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है।

हाई-टेक इंजीनियरिंग के निदेशक मंदीप वर्मा ने इस आविष्कार की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि अगर यह तकनीक सफल होती है, तो यह भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में क्रांति ला सकती है और देश को हरित ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम उठाने में मदद कर सकती है। छात्रों की इस पहल से भविष्य में ईवी वाहनों का और भी व्यापक उपयोग हो सकता है, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आएगी।

जाति जनगणना की जरूरत क्यों?

राम पुनियानी

हाल के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अन्य कारकों के अलावा इस मुद्दे ने भी इंडिया गठबंधन के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में अपना योगदान दिया था। भाजपा के गठबंधन साथी नीतीश कुमार बिहार में पहले ही जाति जनगणना करवा चुके हैं, हालांकि इस मुद्दे को अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है।

भाजपा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है और अपने इस विरोध को उसने मुस्लिम विरोध का जामा पहनाया है। भाजपा का उद्देश्य है जातिगत ऊंच-नीच को बनाए रखते हुए हिंदुओं को एक करना। मंडल पार्टियां कई मामलों में सफल रहीं, मगर उनमें से कुछ ने अपने संकीर्ण हितों की खातिर मनु की राजनीति से समझौता कर लिया। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं, मगर अपनी दो भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान आम लोगों की स्थिति देखने के बाद राहुल गांधी जाति जनगणना के प्रबल समर्थक बन गए हैं। विभिन्न जातियों की आबादी, आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है। जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें इसका लाभ दिलवाना सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है'

हाल के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अन्य कारकों के अलावा इस मुद्दे ने भी इंडिया गठबंधन के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में अपना योगदान दिया था। भाजपा के गठबंधन साथी नीतीश कुमार बिहार में पहले ही जाति जनगणना करवा चुके हैं, हालांकि इस मुद्दे को अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है। राहुल गांधी ने केन्द्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रभावी ढंग से जाति जनगणना की मांग उठाई थी। उन्होंने 'हलवा' का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि बजट तैयार करने वाले मुख्यतः ऊंची जातियों के हैं और बजट के लाभार्थी केवल चंद उच्च वर्ग के लोग हैं। जाति जनगणना आवश्यक है। कारण यह कि आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण दशकों पहले किया गया था और तब से लेकर अब तक विभिन्न जातियों की कुल आबादी की हिस्सेदारी में काफी परिवर्तन आ चुका है। मौजूदा सत्ता जिस विचारधारा की है, वह सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाकर हाशियाकृत समुदायों को अन्य समुदायों के समकक्ष लाने के प्रयासों के खिलाफ है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाने मात्र से दलितों की सामाजिक समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि बेहतर आर्थिक स्थिति से सामाजिक स्थिति में भी बेहतरी आती है। भारतीय समाज जाति व्यवस्था के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ है।

इसके चलते जाति प्रथा के पीड़ितों को सामाजिक न्याय, सम्मान और गरिमा मिले, यह सुनिश्चित करवा पाना आसान नहीं है। दलितों को सम्मान और समानता दिलवाने का संघर्ष बहुत लम्बा और कठिन रहा है। इस दिशा में पहला प्रयास ज्योतिबा फुले ने किया था। उन्हें अहसास था कि जाति प्रथा हिन्दू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। चूंकि दलितों को पढने-लिखने नहीं दिया जाता था, इसलिए फुले ने दलितों के लिए स्कूल खोले। जातिगत पदक्रम को बनाए रखने में लैंगिक असमानता की भी अहम भूमिका है, अतः सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। जातिगत व लैंगिक समानता की स्थापना के ये प्रयास करीब एक सदी पहले किए गए थे। अम्बेडकर ने इन वर्गों को और जागरूक किया। दलितों को समझ में आया कि जमींदार और पुरोहित की जोड़ी, जिसे महाराष्ट्र में शेठजी-भट्टजी कहा जाता है, उनकी सबसे बड़ी पीडक़ है। इसी के चलते ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले इस आन्दोलन की राह आसान नहीं रही। उच्च जातियों के लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने के गांधीजी के प्रयासों से पहले ही परेशान थे। दलितों की समान अधिकारों की मांग ने उच्च जातियों को और विचलित कर दिया। उच्च जातियों के श्रेष्ठी वर्ग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था हिन्दू राष्ट्र की स्थापना, जो मनुस्मृति पर आधारित है। आरएसएस ने भारत के संविधान का इस आधार पर विरोध किया था कि उसमें भारत के स्वर्णिम अतीत के मूल्यों को जगह नहीं दी गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का असर धीरे-धीरे समाज पर पडने लगा। इसके साथ ही अफवाहें फैलाने का क्रम भी शुरू हो गया। आरक्षण से लाभान्वित होने वालों को सरकारी दामाद कहा जाने लगा और यह तर्क दिया गया कि वे जिन पदों पर काबिज हैं, वे उनके योग्य नहीं हैं। यह भी कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था योग्य युवाओं की राह में रोड़ा है। ऊंची जातियों के लोगों का गुस्सा सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया। माधवसिंह सोलंकी के केएचएएम या खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) गठबंधन पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सन् 1981 में गुजरात में दलित विरोधी हिंसा भडक़ गयी। अध्येता अच्युत याग्निक लिखते हैं, 'शिक्षित मध्यम वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, बनिया और पाटीदार शामिल हैं, ने 1981 में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।'

सन् 1985 में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ एक बार फिर गुजरात में दलित विरोधी हिंसा हुई। इसी समय, विश्व हिन्दू परिषद ने राममंदिर आन्दोलन को बढ़ावा देना शुरू किया और लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा शुरू की। वीपी सिंह, जिनकी सरकार एक ओर भाजपा तो दूसरी ओर वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही थी, ने अपनी गद्दी बचाने की खातिर मंडल आयोग की रपट को लागू कर दिया और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), जो आबादी का 55 प्रतिशत हैं, को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। ऊंची जातियां मंडल आयोग के खिलाफ थीं, मगर चुनावी कारणों से भाजपा मंडल का सीधे विरोध नहीं कर सकती थी। उसने रथयात्रा को सफल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। इस यात्रा को मंडल विरोधी उच्च जातियों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। मंडल का विरोध करने के लिए यूथ फॉर इक्वालिटी जैसी संस्थाएं उभर आईं। मंडल राजनीति से शरद यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता उभरे।

भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, 'वे मंडल लाए तो हम बदले में कमंडल लाए।' भाजपा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है और अपने इस विरोध को उसने मुस्लिम विरोध का जामा पहनाया है। भाजपा का उद्देश्य है जातिगत ऊंच-नीच को बनाए रखते हुए हिंदुओं को एक करना। मंडल पार्टियां कई मामलों में सफल रहीं, मगर उनमें से कुछ ने अपने संकीर्ण हितों की खातिर मनु की राजनीति से समझौता कर लिया। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं, मगर अपनी दो भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान आम लोगों की स्थिति देखने के बाद राहुल गांधी जाति जनगणना के प्रबल समर्थक बन गए हैं। विभिन्न जातियों की आबादी, आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है। जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें इसका लाभ दिलवाना सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। जहां इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग का खुलकर समर्थन कर रहा है, वहीं एनडीए का मुख्य घटक दल भाजपा इस मांग की पूर्ति की राह में हरसंभव रोड़ा अटकाएगा। इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन, सभाएं आदि कर इस मांग की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। दलित जातियों को न्याय दिलाने के लिए जाति जनगणना करना जरूरी है और उसी हिसाब से कोटा तय हो।

संपादक की कलम से

सर्वोच्च अदालत के भरोसे

भारत का लोकतंत्र सर्वोच्च अदालत के भरोसे है। वह ही आम आदमी को, अंततः, इंसाफ देती है। यदि सर्वोच्च अदालत न होती, तो देश का आम आदमी कराहते, चिल्लाते, इधर-उधर धक्के खाते हुए जीवन के अंत तक पहुंच सकता था! भारत में भी 'जंगल-राज' का माहौल होता! आज सर्वोच्च अदालत है, तो आम आदमी की उस तक पहुंच बेहद पेचीदा और महंगी है। ऐसे मु_ी भर मामले होंगे, जिनका शीर्ष अदालत स्वतः संज्ञान लेती है और फिर पीड़ित पक्ष की लड़ाई लड़ते हुए उसे न्याय देने की कोशिश करती है। लोकतंत्र की जिम्मेदारी और जवाबदेही न्यायपालिका की ही नहीं है। उसके लिए विधायिका की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन विधायक हो अथवा सांसद हो, उन्हें इस जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है। बस, उन्हें ईवीएम का बटन दबाने के लिए ही जनता की दरकार है, लिहाजा वे पांच साल के कार्यकाल के बाद, कुछ दिनों के लिए, जनता की मनुहार और गुहार करते हैं। उसके बाद जनता की मदद का संदर्भ आता है, तो वे गायब हो जाते हैं। जनता के एक-एक वोट से ही विधायक और सांसद चुने जाते हैं। हमें लगता है कि बस, जनता का दायित्व वोट तक सिमट कर रह गया है। अब औसत मतदाता, अर्थात देश का नागरिक, 'ह्यूमन वोटिंग मशीन' बनकर रह गया है। अदालतों को जनता के वोट नहीं चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों के भीतर आम आदमी, न्याय और सामाजिक-विधिक व्यवस्था अब भी जिंदा हैं। वे देश को 'केला गणतंत्र' बनने से बचाना चाहते हैं। वे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। वे अपराधियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों, हत्यारों और माफिया आदि को कानून के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने और दंडित करने के पक्षधर हैं। कोलकाता अस्पताल रेप-मर्डर कांड को ही लें। सर्वोच्च अदालत देश भर के डॉक्टरों की लड़ाई लड़ रही है, लिहाजा उसकी आग्रहपूर्ण अपील पर डॉक्टरों और उनके संगठनों ने हड़ताल खत्म कर दी है। अदालत का यह आग्रह मानवीय सरोकार वाला था, क्योंकि असंख्य मरीज इलाज के अभाव में तड़प रहे थे। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। शायद कोई त्रासदी हुई भी हो! डॉक्टरों को भी, अंततः, मानवीय दायित्व का एहसास हुआ। इस केस का सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है।

न्यायिक पीठ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार और निर्मम हत्या की सुनवाई तो कर रही है। बंगाल की सरकार और पुलिस की नालायकी, लापरवाही, अराजकता, सांठगांठ के मद्देनजर उन्हें जवाबदेही पर टांग भी दिया है। इसके साथ-साथ अस्पतालों की चाक-चौबंद सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं। वह राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से संवाद कर अकाट्य सुरक्षा-तंत्र लागू करेंगे। कोलकाता के दागदार अस्पताल में सीआईएसएफ के जवान तैनात हो चुके हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों की 36 और 48 घंटे की निरंतर ड्यूटी को 'अमानवीय' करार दिया है। जाहिर है कि शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से यह व्यवस्था भी बदलेगी। यदि एक शिक्षित और पेशेवर व्यक्ति की नियति यही है, तो वह शिक्षा और हुनर बेमानी हैं। सर्वोच्च अदालत ने करीब 24 लाख छात्रों की नीट परीक्षा के संदर्भ में भी कमाल का फैसला दिया। शाहबानो से तीन तलाक और मौजूदा यौन दरिंदगी के मामलों तक सर्वोच्च अदालत ने ही आम आदमी और समाज को बचाया है। जन-प्रतिनिधियों की संसद ने या तो शीर्ष अदालत और संविधान पीठ के फैसले पलटे हैं अथवा सदनों में शोर मचाया है। क्या जन-प्रतिनिधि आम आदमी को इसी तरह बचाएंगे और अपने मतदाता की रक्षा करेंगे। कोलकाता रेप-मर्डर केस में राजनीति दोफाड़ हुई है और उंगलियां तोड़ देने तक की हुंकार भरी गई है। सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड सरीखे मुद्दों पर फैसला दिया है और पूरी विधायिका, कार्यपालिका को बेनकाब किया है।

कविता

आर्थिक डेस्टिनेशन-7

हिमाचल का आर्थिक हिसाब जिन हिस्सों में बंटा है, वहां सरकारी कर्मचारियों का किरदार हमेशा सर्वोपरि रहा। सरकारों का आगमन और प्रस्थान हमेशा इस वर्ग के बाहुपाश में रहा और जाहिर तौर पर नीतियां भी इसी के काबिल बनने की दुहाई देती रहीं। जयराम से सुक्खू सरकार के बीच कर्मचारी वर्ग का अंतर मापने वालों के लिए सचिवालय कर्मियों का हल्ला आंखें खोल सकता है। हम इसे कर्मचारी सियासत में नहीं, बल्कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में देखना चाहते हैं। कर्मचारियों का मोहल्ला कभी संतुष्ट हुआ नहीं, प्रदेश की सारी शिकायतें यहीं ठहर गईं। खैर इस बार का टकराव चुगली कर रहा है। यह सत्ता के लाभार्थियों में फर्क चुन रहा है। उन्हें महंगाई भत्ता चाहिए और एरियर का सैलाब चाहिए, लेकिन वे राज्य की फिजूलखर्ची में अपना पक्ष रख रहे हैं। यही पक्ष ओल्ड पेंशन बनाम माननीयों की पेंशन में भी उठा था। इस नुमाइश में तेरा मेरा नहीं, बल्कि सुविधाओं का बसेरा है। यानी एक हाथ दो, दूसरे से ले लो। कर्मचारी जब वोटर बन जाता है, तो सत्ता का पक्ष बदल जाता है। सचिवालय में प्रदेश बसता है, यह यकीन हो या न हो। प्रश्न सचिवालय में आकर प्रदेश भर के टकरा जाते हैं, लेकिन इस दर्रे की आफत में सरकार आती और बदल जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कार्यसंस्कृति सचिवालय में हो, तो हम किफायत से अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां कर्मचारी, अधिकारी और मंत्रियों के बीच प्रदेश का बजट झगड़ रहा है, तो फिजूलखर्ची की खिचड़ी में उबाल आ गया। कर्मचारियों ने फिजूलखर्ची की खिचड़ी का ढक्कन उठाया, तो मालूम हुआ कि सत्ता के घरौंदे में पंछी कितना अनाज बर्बाद करते हैं। कर्मचारियों ने शिमला की शानोशौकत में सत्ता की बदनाम गलियों का जिक्र किया है।

ये गलियां प्रदेश को महकता हुआ गुलदस्ता बना देती हैं, जहां सरकारी व्यय की चकाचौंध में सरकारी मकान महल बन जाते हैं और गाडियां सत्ता के हाथी घोड़े बनकर मुकुट धारण कर लेती हैं। सचिवालय कर्मचारियों के संघर्ष ने आर्थिक तर्क पैदा किए हैं, लेकिन यह एकतरफा फार्मूला नहीं, बल्कि पलट कर देखें तो हिमाचल का एक दूसरी गागर भी है जहां निजी क्षमता का सागर राजस्व पैदा कर रहा है। एक निजी कंपनी के चालक-परिचालक न केवल अपने मालिक की वित्तीय व्यवस्था का संतुलन बनाते हैं, बल्कि राज्य की कर अदायगी में आर्थिक व्यवस्था भी करते हैं। सरकारी बसों का स्टाफ और प्रबंधन इसके मुकाबले 1966 करोड़ का घाटा पैदा कर चुका है। हिमाचल में पांच करोड़ पर्यटक आ भी जाएं और एडीबी के सहयोग से पालमपुर में टूरिस्ट विलेज बस भी जाए, इससे एचपीटीडीसी के सरकारी होटलों को क्या फर्क पड़ेगा, जबकि निजी होटल का कर्मचारी अपने फर्ज में यह भी जोड़ लेता है कि उसका संस्थान घाटा न उठाए, लेकिन सरकारी तहजीब के कारण एचपीडीसी का घाटा 126 करोड़ पहुंच गया है। प्रदेश की आर्थिकी में सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी का अंतर अगर सचिवालय समझ ले तो मालूम हो जाएगा कि जिस बजट पर कर्मचारी किस्तें मांग रहे हैं या साहबों की कोठियां बड़ी हो रही हैं, उसके योगदान में निजी क्षेत्र के पंद्रह लाख कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक निजी स्कूल अपने लाभ से अध्यापकों को दिहाड़ी देता है। एक निजी अस्पताल अपने मेडिकल स्टाफ की योग्यता से इतना योग्य कैसे हो जाता है कि इसके तमाम खर्चे लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। क्या किसी सरकारी मेडिकल कालेज, अस्पताल, स्कूल, कालेज या विश्वविद्यालय की सरकारी कार्यसंस्कृति में इतना दम है कि अपने दम पर इन्हें आत्मनिर्भर बना दे। कहना न होगा कि हिमाचल को अपनी नीतियों से अगर आत्मनिर्भर या आर्थिक डेस्टिनेशन बनना है, तो निजी क्षेत्र और प्राइवेट कर्मचारियों को अपना आर्थिक ब्रांड एंबेसेडर बनाए। -क्रमशः

रमेश धवाला

निर्मम ममता और गर्तगामी समाज

निर्भया मामले के बाद लगा था कि हालात सुधरेंगे, किन्तु नहीं। केवल कानून सख्त बना देने से काम होने वाला नहीं। कानून को लागू करने वाली मशीन भी गंभीर होनी चाहिए। और अंत में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे बच्चों को नैतिक तरबीयत जो घर से ही दी जा सकती है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कानून तो उल्लंघन करने वालों के लिए ही है। यदि आपराधिक सोच ही कम होती जाए, तो ऐसी घटनाएं होना ही कम हो जाएंगी। यह काम तो घरों से ही शुरू होना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि पीड़ित डाक्टर को न्याय मिलेगा और आगे के लिए भी सुधार का मार्ग सुनिश्चित हो सकेगा'

कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की जघन्य हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। पूरा देश हतप्रभ है कि यह हो क्या रहा है। जिस तरह की संभावनाएं सीबीआई जांच में उभर कर आ रही हैं, वे सोच से परे की गिरावट का परिदृश्य पैदा करने वाली हैं। एक चिकित्सा संस्थान कैसे यौन अपराध का रैकेट चालक, ड्रग तस्करी में लिप्त और अवैध अंग तस्करी जैसी जघन्य गतिविधियों का ठिकाना हो सकता है? उस अपराध की शिकार महिला से बलात्कार के पीछे के कारणों में यदि अंग तस्करी और ड्रग तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियां भी जुड़ी हों तो यह मामला अति गंभीर श्रेणी का हो जाता है, जिस पर से पर्दा उठना अत्यावश्यक हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया में मददगार होने की प्रशासनिक जिम्मेदारी है, वही प्रशासन अपराधियों का संरक्षण करता दीखता है। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का व्यवहार कितना ओछा और हैरान करने वाला है, जब वह प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय स्वयं यात्रा निकाल कर घटना का विरोध करने निकल पड़ती हैं। यह समझ नहीं आता कि वह किसका विरोध कर रही हैं और किससे सजा दिलाने की मांग कर रही हैं। यह तो राज्य सरकार का ही कार्य है और वही राज्य की मुखिया हैं। शक के दायरे में कॉलेज के प्रिंसिपल का व्यवहार भी है। उसे बचाने के प्रयास क्यों किए जा रहे है। जिसे हत्या की सूचना पुलिस को समय पर न देने का जिम्मेदार ठहरा कर निलंबित किया जाना चाहिए था, उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना कर पुरस्कृत करने या संरक्षित करने का कार्य हैरान करने वाला है।

हत्या के प्रकट मामले को आत्महत्या क्यों दिखाने के प्रयास हुए हैं? इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका क्यों संदिग्ध बनी हुई है? प्रथम दृष्टया हत्या दिखने वाले मामले को पुलिस आत्महत्या दिखाने का प्रयास करे तो यह बहुत गंभीर मामला बनता है। पूरे केस की जांच करके सच्चाई को न्यायालय के सामने अपराधी को दंडित करने के लिए पेश करना, असल जिम्मेदारी पुलिस की ही है। आरंभिक जांच में ऐसी कोताही बरतना अक्षम्य है। जांच के लिए घटनास्थल पर सबूतों को इकट्ठा करना, सबूतों को संरक्षित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इसमें पुलिस सोई हुई क्यों लगती है? क्यों घटना स्थल को खुला छोड़ कर साक्ष्यों को नष्ट करने का मौका अपराधी तत्वों को दिया गया। जांच कार्य के बीच में ही घटना स्थल के साथ निर्माण कार्य के लिए तोडफ़ोड़ करने के पीछे क्या मंशा है? ऐसे कई संदेह पैदा करने वाले तथ्य खबरों से निकल कर आ रहे हैं। वैसे ममता बैनर्जी के कार्यकाल में अराजकता के अनेक मामले पहले भी उभरते रहे हैं। संदेश खाली की घटना तो अभी ताजा ही है। चुनावों के बाद की हिंसा में विरोधियों को प्रताड़ित करने की छूट और उस पर राजनेताओं और प्रशासन की चुप्पी, पंचायत चुनावों के बाद हुई खुली हिंसा पश्चिमी बंगाल में प्रशासन की निष्पक्षता को संदिग्ध बनाते हैं। जहां विरोधी दलों के समर्थकों के साथ हिंसक प्रतिकार की छूट प्रशासन द्वारा दी जाती है। यहां तक कि गवर्नर और राज्य का उच्च न्यायालय भी इस पर टिप्पणियां करते रहे हैं। कानून व्यवस्था के मामलों में इस तरह का भेदभाव व्यवस्था को कमजोर करता है और आपराधिक भूमिका वाले लोगों के हौसले बढ़ाता है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को इससे बचना चाहिए। प्रजातंत्र का मूल तो कानून का शासन है, जिसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। शायद बंगाल वामपंथी शासन के समय की इलाका दखल संस्कृति से अभी उबर नहीं पाया है, या ममता बनर्जी ने भी उसी कार्य प्रणाली को अपना लिया है ताकि विरोध के स्वरों को उठने ही न दिया जाए। यह एक दलीय शासन की स्थापना की इच्छा का द्योतक है। विरोधी पक्ष भी ऐसी स्थितियों में राजनीतिक लाभ के चक्कर में पडने लग जाता है। एक ऐसी अस्वस्थ बहस होने लग जाती है कि आपके शासित राज्य में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सच में ऐसा हो भी रहा है। अभी देहरादून में एक मानसिक रूप से कमजोर लडक़ी के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। अपराधी पकड़े गए हैं, किन्तु मेरी गलती और तेरी गलती करके गलती माफ नहीं की जा सकती।

असल बात यह है कि जहां भी ऐसी घटना हो, वहां अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी दलगत ओछी राजनीति से ऊपर उठ कर पूरी की जानी चाहिए। निर्भया मामले के बाद लगा था कि हालात सुधरेंगे, किन्तु नहीं। केवल कानून सख्त बना देने से काम होने वाला नहीं। कानून को लागू करने वाली मशीन भी गंभीर होनी चाहिए। और अंत में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे बच्चों को नैतिक तरबीयत जो घर से ही दी जा सकती है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कानून तो उल्लंघन करने वालों के लिए ही है। यदि आपराधिक सोच ही कम होती जाए, तो ऐसी घटनाएं होना ही कम हो जाएंगी। यह काम तो घरों से ही शुरू होना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि पीड़ित डाक्टर को न्याय मिलेगा और आगे के लिए भी सुधार का मार्ग सुनिश्चित हो सकेगा। तब तक जागते रहें। ताजा खबरों के अनुसार ममता बैनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। यह ठीक बात है, पर अगर कानून को लागू करने वाली मशीनरी को ही जंग लग जाएगी, तो इसका क्या लाभ होगा? समाज को जागरूक करना होगा।

कुलभूषण उपमन्यु

नेता खड़ा बाजार में!

वैसे तो नेता कहीं भी खड़ा हो सकता है। दारू की दुकान के बाहर भी खड़ा हो सकता है और वहीं अपने मित्रों से भी गुफ्तगू कर सकता है। नेता इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। नेता कोर्ट में भी खड़ा हो सकता है और माननीय जज साहब के सामने अपनी बेगुनाही के सबूत देने में अपनी जी जान लगा सकता है। नेता हाईकमान के सामने भी झुक कर खड़ा हो सकता है और झुकते हुए ही पैसों से भरा ब्रीफकेस हाईकमान के चरणों में रख सकता है। नेता किसी भी आंदोलन में सबसे आगे खड़ा होकर भाषण झाड़ सकता है। नेता सत्ता में आने के बाद पब्लिक के सवालों से बचने के लिए घंटों बाथरूम में भी खड़ा हो सकता है। खड़े-खड़े नहा भी सकता है। खड़े-खड़े मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। बाथरूम में खड़े-खड़े ही मोबाइल कान पर लगाकर कानून व्यवस्था का जायजा भी ले सकता है। बाढ़ पीड़ितों की आंखें सुन सकता है। वहीं से सांत्वना व्यक्त कर सकता है। दो-चार बाढ़ में बहे लोग बचा लिए गए हों, तो वहीं से ही बधाई संदेश दे सकता है। लेकिन अगर नेता बाजार में आकर खड़ा हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। जैसे मदारी को देखने के लिए भीड़ इक_ा हो जाती है, वैसे बाजार में खड़ा नेता आकर्षण का केंद्र बन जाता है। बाजार चाहे कैसा भी हो, नेताजी की उपस्थिति मूल्यवान हो जाती है। अगर बाजार में सामाजिक मान-मर्यादाओं की नीलामी लग रही हो और नेताजी वहां मौजूद हों, तो मर्यादाओं को चार चांद लग जाते हैं। अगर बाजार में आदर्शों की होली जलाई जा रही हो और नेताजी वहां खड़े हों, तो आदर्शों की महिमा अपरंपार हो जाती है। अगर बाजार में सिद्धांत और मूल्य ताक पर रखे जा रहे हों, और नेताजी वहां मौजूद हों तो लोकतंत्र झूमने लगता है। नेताजी बाढ़ पीड़ित इलाके में हों तो बाढ़ पीड़ितों के दर्द की बजाय नेताजी का दौरा कैमरे के फोकस में आ जाता है। नेताजी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हों तो धरती पर उनके फोटो प्रकाशित होने लगते हैं और नेताजी को राजभाट मीडिया जनता का मसीहा करार देने लगता है। लेकिन नेताजी अब बाजार में हैं। अपने कीमती समय से समय निकाल कर बाजार में आए हैं।

बाजार में उनकी कोई बोली नहीं लगनी है। कोई खरीददार उनकी बोली लगाने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद नेताजी बाजार में खड़े हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ खड़े हैं। कैमरे उनके चेहरे पर फोकस हैं। पब्लिक हैरान होकर उनके इस अवतार को देख रही है। पब्लिक ने अभी तक इलेक्शन बीत जाने के बाद नेताजी को गायब होते देखा है। लेकिन पहली बार नेताजी बाजार में खड़े हैं और पब्लिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। कुछ लोगों को नेताजी साक्षात देवदूत लग रहे हैं। क्योंकि वोटो का मौसम नहीं है, इसके बावजूद नेताजी बाजार में खड़े हैं। लोग आश्चर्यचकित होकर आंखों ही आंखों में एक-दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि कहीं सतयुग तो नहीं आ गया। कई बार युग बदलने की लोगों को भनक नहीं लगती। गूगल इसके बारे में कोई पूर्ण जानकारी नहीं देता। पब्लिक गफलत में रह जाती है। पब्लिक के मन में यह धारणा होती है कि नेताजी इलेक्शन जीतने के बाद उसी तरह गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन यहां तो साक्षात सींग भी दिख रहे हैं और नेता भी दिख रहा है। यही अचरज का विषय हो गया है। नेताजी बाजार में आए हैं तो निश्चित रूप से दालों के भाव पूछेंगे। सब्जियों के भाव पूछेंगे। जब सब चीजों के भाव पूछेंगे तो नेताजी इमोशनल हो जाएंगे। प्याज के दाम पूछ कर उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। टमाटर के दाम पूछ कर उनकी सिट्टी-पिटी गुम हो जाएगी। अदरक की कीमत जानकार होश फाख्ता हो जाएंगे। नेताजी मन ही बना खुद को कोसने लगेंगे कि अच्छे भले अपनी वातानुकूलित कोठी में बैठे थे। काहे को बाजार आने का पंगा ले लिया। बाजार आकर आटे-दाल का भाव पता चल गया। महंगाई का दर्द पता चल गया। नेताजी सोच रहे हैं कि बाजार आने की बजाय सरकारी खर्चे पर विदेश का टूर लगा लिया होता तो यह लोक और परलोक संवर जाता।

गुरमीत बेदी

अमेरिका से ब्याज दरों में कटौती का संकेत मिला, भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर?

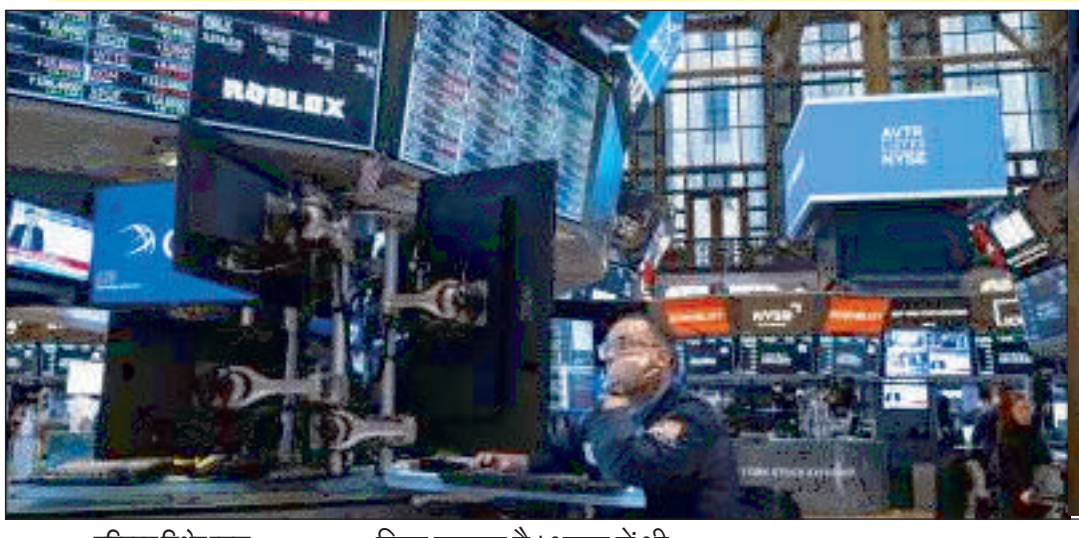

परिवहन विशेष न्यूज

पॉवेल के ब्याज दरों में कटौती के संकेत के बाद अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त रैली दिखी। शुक्रवार को Dow Jones Industrial Average 1.14 प्रतिशत और Nasdaq में 1.47 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट पर भी इसका असर दिख सकता है। भारत में भी मंहगाई धीरे-धीरे काबू में आ रही है। ऐसे में रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोच सकता है।

नई दिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को एडजस्ट करने का वक्त आ गया है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अमेरिका का केंद्रीय सितंबर में ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। इस संकेत के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया। इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी दिख सकता है।

ब्याज दरों में कितनी कटौती होगी?

पॉवेल ने कहा, 'मुद्रास्फीति के लिए जोखिम कम हो गया है।' अधिकांश एनालिस्ट का मानना है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती कर सकता है। हालांकि, कुछ ट्रेडर्स 0.5 फीसदी तक की कटौती की उम्मीद जता रहे हैं। अमेरिका में चिंताजनक वित्तीय आंकड़ों ने आर्थिक मंदी की आशंकाओं को जन्म दे दिया था। लेकिन, अब बेरोजगारी और महंगाई घटने से राहत मिली है।

कोरोना महामारी के बाद से ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए ब्याज दरों को 23 साल के उच्चतम स्तर पर बनाए रखा है। यूरोप के विकसित बाजारों ने पहले ही ब्याज दरें घटाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के बाद कई अन्य देश भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं।

भारतीय बाजार पर क्या असर होगा?

पॉवेल के ब्याज दरों में कटौती के संकेत के बाद अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त रैली दिखी। शुक्रवार को Dow Jones Industrial Average 1.14 प्रतिशत और Nasdaq में 1.47 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट पर भी इसका असर दिख सकता है। भारत में भी मंहगाई धीरे-धीरे काबू में आ रही है। ऐसे में रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोच सकता है।

अगर ब्याज दरें कम होती हैं, तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। इससे व्यापार और खपत को बढ़ावा मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज हो सकती है, जिसके सुस्त पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सोना-चांदी के जेवरों के निर्यात पर शुल्क वापसी दर घटी, बजट 2024 में किया गया था एलान

परिवहन विशेष न्यूज

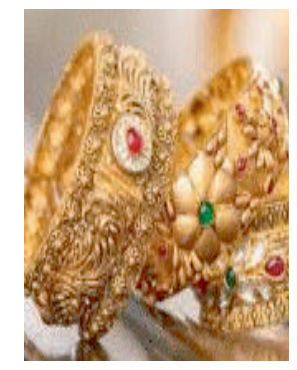

सोने के जेवरों के निर्यात पर शुल्क वापसी दर को 704.1 रुपये प्रति ग्राम से घटाकर 335.5 रुपये प्रति ग्राम किया गया है। सी तरह चांदी के आभूषणों और चांदी की वस्तुओं की दर को घटाकर 4468 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। शुल्क वापसी योजना निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर चुकाए गए आयात शुल्क और आंतरिक करों को वापस करती है।

नई दिल्ली। सरकार ने सोना और चांदी के जेवरों के निर्यात पर शुल्क वापसी दरों (ड्राबैक रेट) में आधे से अधिक की कटौती की है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि बजट में इन धातुओं के आयात शुल्क में की गई कमी के समायोजना के लिए यह कटौती की गई है। सोने के जेवरों के निर्यात पर शुल्क वापसी दर को 704.1 रुपये प्रति ग्राम से घटाकर 335.5 रुपये प्रति ग्राम किया गया है।

इसी तरह, चांदी के आभूषणों और चांदी की वस्तुओं की दर को घटाकर 4,468 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। शुल्क वापसी योजना निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर चुकाए गए आयात शुल्क और आंतरिक करों को वापस करती है। बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान रत्न और आभूषण निर्यात 7.45 प्रतिशत घटकर 9.1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश किए गए आम बजट में शुल्क वापसी दरों (ड्राबैक रेट) को कम करने का प्रस्ताव पेश किया था।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 350 रुपये घटकर 73,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी का भाव 200 रुपये घटकर 87,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया, जो पिछले दिन 87,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 350 रुपये घटकर 73,450 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि गुरुवार को यह 73,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

मेगा बिजली ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच ग्रिड व ट्रांसमिशन सेक्टर पर चर्चा

अमेरिका इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ ही वित्त सुविधा देने को भी तैयार है। दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में कई स्तरों पर बातचीत शुरू हुई है। भारत व अमेरिका मिलकर कम ऊर्जा खपत से चलने वाले एयर-कंडीशनरों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। मेगा बिजली ट्रांसफॉर्मर भी इसी तरह का क्षेत्र है।

नई दिल्ली। भारत में बिजली की खपत जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए यहां मेगा बिजली ट्रांसफॉर्मर की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन, भारत के पास इस तरह के ट्रांसफॉर्मर बनाने की तकनीक नहीं है। अब अमेरिका ने इस क्षेत्र में मदद करने की पहल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के वरिष्ठ सलाहकार (अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नीति) जान पेडेस्टा ने पिछले दो दिनों के दौरान भारत के बिजली मंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई मुलाकात में इस बारे में विस्तार से विमर्श किया।

अमेरिका इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ ही वित्त सुविधा देने को भी तैयार है। दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में कई स्तरों पर बातचीत शुरू हुई है। दैनिक जागरण ने कुछ सप्ताह पहले यह खबर प्रकाशित की थी कि किस तरह से भारत व अमेरिका मिलकर कम ऊर्जा खपत से चलने वाले एयर-कंडीशनरों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। मेगा बिजली ट्रांसफार्मर भी इसी तरह का क्षेत्र है।

दोनों देशों के बीच ग्रिड व ट्रांसमिशन सेक्टर को अत्याधुनिक बनाने पर भी बात हुई है। इससे भारत के मौजूदा ग्रिड ढांचे को अत्याधुनिक बनाना उद्देश्य होगा, जिससे भविष्य की मांग के मुताबिक यह काम कर सके। भारत व अमेरिका बैट्री स्टोरेज में भी विमर्श कर रहे हैं।

पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम छोड़ती हैं नौकरी, कंपनियों के बोर्ड रूम में भी हिस्सेदारी

Corporate Sector में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम नौकरी छोड़ती हैं। वहीं कंपनी के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। स्थायी कर्मचारियों में भी केवल 20.81 फीसदी ही महिलाओं की हिस्सेदारी है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

> मंत्रालय द्वारा डेटा के अनुसार स्थायी कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी केवल 20.81 फीसदी है। वहीं, केएमपी यानी की- मैनेजेरियल पोस्ट पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14.08 फीसदी है। यह स्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी से भी काफी कम है। कॉरपोरेट जॉब को लेकर ग्रांट थॉन्टन ने रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एवरेज पर सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पर महिलाओं की हिस्सेदारी 33.5 प्रतिशत है। वहीं, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो केवल 7 महिलाएं हैं जो 8.4 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा कमाती है।

नई दिल्ली। कॉरपोरेट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने डेटा जारी किया। इस डेटा के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 0.35 फीसदी की दर से महिलाओं ने नौकरी छोड़ी हैं। वहीं पुरुषों के मामले में यह दर 0.42 फीसदी थी।

भले ही नौकरी छोड़ने के मामलों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम नौकरी छोड़ती हैं। लेकिन, कंपनियों के बोर्ड रूम में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। लिस्टिड कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 18.67 फीसदी है।

बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी के आंकड़ें ग्लोबल बेंचमार्क से काफी कम है। ग्लोबल बेंचमार्क के अनुसार कंपनी के बोर्ड में कम से कम 30 फीसदी महिला की भागीदारी होनी चाहिए। इस दर को प्रतिनिधित्व मानक माना जाता है।

मैनेजेरियल पोस्ट पर महिलाओं की कम भागीदारी

मंत्रालय द्वारा डेटा के अनुसार स्थायी कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी केवल 20.81 फीसदी है। वहीं, केएमपी यानी की- मैनेजेरियल पोस्ट पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14.08 फीसदी है। यह स्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी से भी काफी कम है।

कॉरपोरेट जॉब को लेकर ग्रांट थॉन्टन ने रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एवरेज पर सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पर महिलाओं की हिस्सेदारी 33.5 प्रतिशत है। वहीं, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो केवल 7 महिलाएं हैं जो 8.4 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा कमाती है।

ईएमए पार्टनर्स ने भी महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 200 कंपनियों में महिलाओं की हिस्सादारी 6.26 फीसदी है।

बढ़ गई महिला बेरोजगारी दर

पीएलएफएस की डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में महिला बेरोजगारी दर में वृद्धि हो गई है। यह अप्रैल-जून तिमाही में 9 फीसदी पहुंच गया। वहीं, पिछली तिमाही में यह 8.5 फीसदी थी। बेरोजगारी दर के साथ महिला वर्क फोर्स में भी गिरावट आई। यह पहली तिमाही में 25.6 फीसदी से घटकर 25.2 फीसदी हो गई। इस दर से साफ पता चल रहा है कि महिलाओं को काम का अवसर नहीं मिला है।

स्व-रोजगार के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी 41.3 फीसदी से कम होकर 40 फीसदी हो गई।

ईपीएफओ डेटा

ईपीएफओ ने हाल ही में एक डेटा जारी किया था। इस डेटा के अनुसार पहली तिमाही में फार्मल सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी हैं। 30 लाख नए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स में से 27.3 फीसदी महिलाएं हैं।

आईपीओ से पहले स्विगी की बड़ी तैयारी, जोमैटो को मिलेगी कड़ी टक्कर

स्विगी ने आखिरी बार 2022 में 10.7 अरब डालर के मूल्यांकन पर पैसा जुटाया था। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जोमैटो से मुकाबले के लिए क्विक कामर्स इंस्टामार्ट कारोबार के विस्तार और ज्यादा वेयरहाउस खोलने पर कर सकती है। जोमैटो की शेयर मार्केट में लिस्टिंग 2021 में लिस्टिंग के बाद दोगुने से भी अधिक हो गया है।

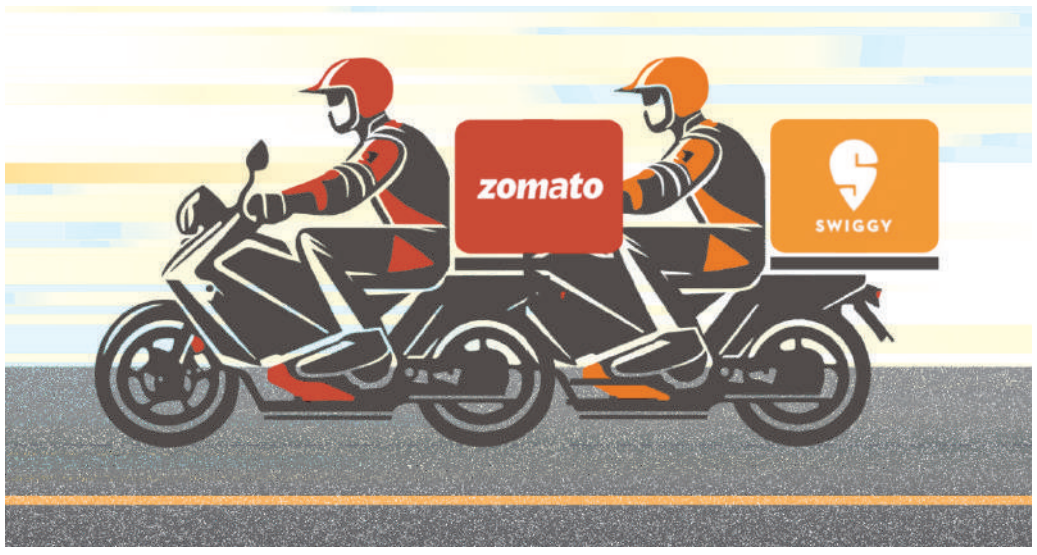

नई दिल्ली। दिग्गज फूड डिलिवरी प्लेटफार्म स्विगी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से पहले अपना मूल्यांकन 15 अरब डॉलर के करीब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी आईपीओ के जरिये बाजार से 8-10 हजार करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह 2024 के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि स्विगी के शेयरधारक अप्रैल में ही आईपीओ के जरिये करीब 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दे चुके हैं। इस संबंध में प्रस्ताव को बाजार नियामकों से एक महीने में मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद आइपीओ की मंजूरी के लिए सार्वजनिक दस्तावेज जमा किए जाएगा।

जोमैटो को टक्कर देने का इरादा

स्विगी ने आखिरी बार 2022 में 10.7 अरब डालर के मूल्यांकन पर पैसा जुटाया था। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जोमैटो से मुकाबले के लिए क्विक कामर्स इंस्टामार्ट कारोबार के विस्तार और ज्यादा वेयरहाउस खोलने पर कर सकती है। जोमैटो की शेयर मार्केट में लिस्टिंग 2021 में लिस्टिंग के बाद दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है। दीपिंदर गोयल के मालिकाना हक वाली कंपनी का मार्केट कैप फिलाहल करीब 28 अरब डॉलर के करीब है।

प्रतिष्ठित ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने अप्रैल में एक रिपोर्ट में बताया कि देश के ऑनलाइन ग्रॉसरी मार्केट में इस समय 45 हिस्सा क्विक कॉमर्स सेगमेंट के पास है। इसकी साइज करीब 5 अरब डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले कुछ साल में यह हिस्सेदारी बढ़कर 70 फीसदी तक हो सकती है।

यह फिलहाल सबसे तेजी से बढ़ता सेगमेंट है। यही वजह है कि जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलिवरी कंपनियां भी इसी पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। जोमैटो का कारोबार बढ़ाने में उसकी क्विक कामर्स यूनिट ब्लिंकिट का काफी अधिक योगदान है।

रिलाइंस-डिज्नी क्रिकेट राइट्स पर अड़े, 10 चैनलों की बिक्री को तैयार; CCI के पाले में गेंद

मर्जर को लेकर रिलायंस की ओर से कहा गया है कि वे क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेंगे। हालांकि रिलायंस-डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने के लिए तैयार हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CEE) से दोनों कंपनियों ने अपनी 71250 करोड़ रुपये में होने वाली मर्जर डील के लिए कुछ रियायतें देने की बात कही थी। CEE ने दोनों कंपनियों से अब तक 100 ज्यादा सवाल पूछे हैं।

नई दिल्ली। Reliance और Disney के मर्जर को लेकर नया अपडेट आया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CEE) से दोनों कंपनियों ने अपनी 71250 करोड़ रुपये में होने वाली मर्जर डील के लिए कुछ रियायतें देने की बात कही थी। कई महीनों से दोनों कंपनियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्री में स्पोर्ट्स दिखाकर यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

नहीं बेचेंगे क्रिकेट राइट्स

Disney-Reliance मर्जर को लेकर रिलायंस की ओर से कहा गया है कि वे क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेंगे। हालांकि, रिलायंस-डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने के लिए तैयार हैं। मर्जर के बाद इनका मुकाबला सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनियों से होना है। Disney-Reliance का लक्ष्य होगा कि ये इन कंपनियों से आगे निकलें।

CEE ने चेताया

दोनों कंपनियों को चेताते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CEE) ने कहा था कि मर्जर के बाद ये अधिकतम क्रिकेट राइट्स पर कंट्रोल कर सकती है, जिससे विज्ञापनदाताओं को नुकसान होगा। CEE को जवाब देते हुए दोनों कंपनियों ने ऐड रेट में बढ़ोतरी न करने का प्रस्ताव रखा है।

दोनों कंपनियों का कहना है क्रिकेट राइट्स के लिए 80 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ऐसे में वो क्रिकेट स्ट्रीमिंग नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि, इस प्रस्ताव पर सीईई ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखना ये होगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद क्या फैसला लेगा।

पहले भी हुए सवाल-जवाब

मर्जर का प्रस्ताव रखने के बाद से CEE ने दोनों कंपनियों से अब तक 100 ज्यादा सवाल पूछे हैं। कंपनियों ने सीईई से कहा है कि वे मार्केट को लेकर पनप रही चिंताओं को कम करने के लिए तैयार हैं। रिलायंस और डिज्नी 10 चैनल भी बेचने के लिए तैयार हैं। मर्जर के बाद 120 चैनलों के साथ विज्ञापन बाजार में इनकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत होने की संभावना है।

महिलाओं के बिना विकसित भारत का संकल्प अधूरा

रिपोर्ट में दावा- वर्कफोर्स में जोड़नी होंगी 40 करोड़ महिलाएं

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वर्कफोर्स में 40 करोड़ अतिरिक्त महिलाएं जोड़नी होंगी। ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 37 प्रतिशत को लगभग दोगुना बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने की जरूरत होगी। हालांकि इसमें महिलाओं के नौकरी खोने की संभावना सात गुना अधिक पाई गई।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। द नज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में 14 लाख करोड़ रुपये का योगदान देने के लिए श्रमबल में 40 करोड़ अतिरिक्त महिलाएं जोड़नी होंगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 37 प्रतिशत को लगभग दोगुना बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने की जरूरत होगी। पिछले कुछ वर्षों के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2047 तक 30 लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है।

पुरुष और महिलाओं के बीच भारी असमानता

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2047 तक केवल 11 करोड़ महिलाएं श्रमबल में होंगी। ऐसे में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला श्रम बल भागीदारी में पर्याप्त बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं के बीच नौकरी की सुरक्षा व सुधार के मामले में भारी असमानता की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के नौकरी खोने की संभावना सात गुना अधिक पाई गई और नौकरी छूटने के बाद भी ठीक न होने की संभावना ग्यारह गुना अधिक पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में कार्यरत लगभग आधी महिलाएं 2020 तक श्रमबल से बाहर हो चुकी थीं।

भागीदारी बढ़ाने के तरीके

महिलाएं मुख्य रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे कि कृषि और विनिर्माण में काम करती हैं, जहां उन्हें सीमित उन्नति का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख तरीके बताए गए हैं। इसमें प्लेटफॉर्म जॉब्स और डिजिटल माइक्रोवर्क के माध्यम से काम को फिर से परिभाषित करने, डिजिटल कॉमर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उद्यमिता के अवसर बढ़ाने और गतिशीलता और डिजिटल पहुंच जैसी बाधाओं को दूर करना शामिल है।

सीरवी समाज कोरेमुला बडेर में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन 26 को

हैदराबाद। कोरेमुला सीरवी समाज कोरेमुला बडेर में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन सोमवार 26 अगस्त को किया जाएगा। सीरवी समाज कोरेमुला बडेर के संरक्षक प्रभुराम परिहारिया अध्यक्ष कालुराम काग सचिव डायाराम लचेटा ने बताया कि भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांय 7 बजे को भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना की जाएगी, इसके अलावा भजन-कीर्तन, रात्रि में 12.05कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव झुला झुलाया जाएगा। सम्मत कार्यकारिणी सदस्यगण व समाज बन्धु।

सीरवी समाज शमशाबाद बडेर में भादवा सुदी बीज महोत्सव व वार्षिक सम्मेलन 5 सितंबर को

सीरवी समाज शमशाबाद स्थित सीरवी समाज की आस्था का केन्द्र श्री आईमाता मंदिर (बडेर) में समाज बन्धुओं के सानिध्य में विशेष मीटिंग आयोजित कर श्री आईमाताजी के 609 वें अवतरण दिवस व दसवां वार्षिक सम्मेलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत भादवा सुदी एकम बुधवार 4 सितंबर रात्रि जागरण व भादवा सुदी बीज (दूज) गुरुवार 5 सितंबर प्रातः वेला में विशेष पूजा- अर्चना व महाप्रसादी कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जायेगा। अध्यक्ष आशाराम गहलोत, सचिव भोलाराम पंवार ने संयुक्त रूप से बताया कि हर वर्ष की भांति समाज बन्धुओं के सानिध्य में दो दिवसीय भादवा सुदी बीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार 4 सितंबर प्रातः वेला मेंश्रीआईमाता मंदिर को विशेष फूलों व लाइटिंग से सजाकर माता जी का विशेष श्रृंगारकर रात्रि 9.11बजे से जागरण आयोजित किया जाएगा। जिसमे भजन कलाकार - माणक चन्द प्रजापत (चावंडिया)एण्ड पार्टी द्वारा माता जी के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित करेंगे।रात्रि जागरण का Youtube चेनल BRS Rajasthani पर लाइव प्रसारण भगवान रामओर उनकी टीम द्वारा किया जाएगा।1 महिला मंडल द्वारा हरजस 08:00 से 9:00 बजे तक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले को अपना नाम दिनांक 29 अगस्त 2024 तक महिला मंडल सचिव महोदय भारती परिहारिया को दिरावे। गणेश वंदना एवं आईमाता जी पुजा अर्चना श्री आईमाता जी की पूर्ण आरती गुरुवार 5 सितंबर प्रातः 9.15 बजे ज्योत प्रज्वलित कर, पुजा अर्चना, स्वागत, समाज बन्धुओं द्वारा माता जी के चरणों में श्रीफल भेंटकर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना, समाज के बाल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रातः 10:30 बजे से धर्मसभा का आयोजन कर अध्यक्ष आशाराम गहलोत की अध्यक्षता में मुख्य अतिथियों, पधारे मेहमानों का स्वागत, कोषाध्यक्ष राजुराम परिहार द्वारा आय-व्यय का विवरण, पदाधिकारियों का सम्मान एवं अपने विचार व्यक्त करना, सचिव भोलाराम पंवार ने समाज में किये गये विकासशील कार्यो का विवरण देंगे, एवं पधारे समाज बन्धुओं व भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में रहेगी। बीज महोत्सव कार्यक्रम में पदाधिकारी व कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य पधारे भक्तों की सेवार्थ उपस्थित रहेंगे। समाज बन्धुओं से निवेदन है कि बीज महोत्सव पर अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर, समाज बन्धु सपरिवार पधारकर कार्यक्रम का लाभ लेवे। अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन भाषण व धन्यवाद प्रस्ताव, महाआरती के पश्चात कार्यक्रम का सम्मापन्न होगा।

महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया निर्देश

केंद्र सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 225 करोड़ रुपये तक के लंबित दावों का भुगतान एक हफ्ते के अंदर करने का निर्देश दिया। 22 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक की।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 225 करोड़ रुपये तक के लंबित दावों का भुगतान एक हफ्ते के अंदर करने का निर्देश दिया। बता दें कि यह आदेश केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 21 अगस्त को नांदेड़ में किसानों के साथ बातचीत के बाद आया है, जहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों के मुद्दे उठाए गए थे।

22 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने फसल काटने के प्रयोगों पर बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लंबित दावों के निपटान का आदेश दिया।

क्या है बीमा कंपनी का नाम?

बयान में बीमा कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया। सेंट्रल टीएसी ने शनिवार को बीमा कंपनी को सात दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का औपचारिक आदेश जारी किया।

इस निर्णय से परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को लाभ होगा, जिसका भुगतान 200 से 225 करोड़ रुपये के बीच होगा।

किसानों ने मंत्री को बताई अपनी समस्या

नांदेड़ की यात्रा के दौरान परभणी जिले के किसानों ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया, जिसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अधिकारियों को समस्या का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया था। त्वरित कार्रवाई से मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, ये सोयाबीन की महत्वपूर्ण खेती के लिए जाना जाता है।

11वीं-12वीं के छात्रों को केंद्र का तोहफा, 'विज्ञान धारा' नाम से नई स्कीम की लॉन्च; आसानी से मिलेगी इंटर्नशिप

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ने और शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा नाम से एक नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। 11 वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों को विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विज्ञान धारा स्कीम के कुल पांच स्तंभ है।

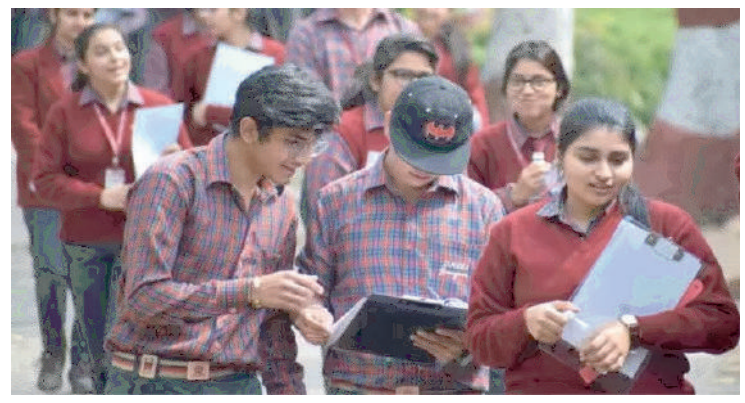

नई दिल्ली। युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ने में जुटी केंद्र सरकार ने शनिवार को इस दिशा में एक और अहम फैसला लिया है। जिसके तहत शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'विज्ञान धारा' नाम से एक नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है।

इन छात्रों को मिलेगी इंटर्नशिप

इस दौरान 11 वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों को विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जहां वह शोध और नवाचार से जुड़ी अपनी अभिरुचि को बढ़ा सकेंगे। इस पूरी स्कीम पर अगले पांच सालों में साढ़े दस हजार करोड़ से अधिक खर्च होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को इस स्कीम को मंजूरी दी है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विज्ञान धारा स्कीम के कुल पांच स्तंभ है।

11वीं -12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को शोध और इनोवेशन के क्षेत्र में इंटर्नशिप प्रदान करना है। स्नातक व परास्नातक स्तर पर फेलोशिप व डॉक्टरेट के और अवसर मुहैया कराना है।

शोध और इनोवेशन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देना है। दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करना भी है।

संयुक्त शोध व प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा मंजूरी देना है। ताकि देश के वैज्ञानिक यहीं रखकर किसी क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम कर सके।

समाज की जरूरत से जुड़े मुद्दों पर नए-नए शोध और प्रोजेक्ट को शुरू करना।

शोध को आगे बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देखने को मिलता है कि शोध तो होता है लेकिन वह जमीन पर नहीं उतर पाता है। इसके चलते लोगों की उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस स्कीम के तहत इस बात की जोर होगा, कि जो शोध कार्य हो उसे जल्द से जल्द लोगों के बीच पहुंचाया जाए।

बायोटेक्नोलॉजी को मजबूती देने सरकार लाएगी नई नीति

बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी संभावना को देखते हुए कैबिनेट ने शनिवार को बायो-ईथ्री (बायोटेक्नालॉजी फॉर इकोनामी, इनवायरमेंट और इंप्लॉयमेंट) नीति लाने का ऐलान किया है। जो सरकार की नेट जीरो और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जैसी पहलों को मजबूती देने का काम करेगी।

इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान के लिए भी नए द्वार खोलेगी, जिसमें न सिर्फ एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी होगी बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। नीति का जिन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस होगा, उनमें खाद्य, कृषि, चिकित्सा, समुद्र, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्र शामिल है।

मथुरा रोड पर सड़क पार करने वालों को जल्द मिलेगी राहत, फुटओवर ब्रिज में एस्केलेटर और लिफ्ट होगी चालू

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा रोड पर प्रगति मैदान के पास दो फुटओवर ब्रिज में एस्केलेटर और एक में लिफ्ट चालू होने जा रही है। इससे लोगों को सड़क पार करने में काफी राहत मिलेगी। अभी सीधे सड़क पार करने से कई बार लोगों की जान को खतरा हो जाता है। दिल्ली सरकार ने सभी फुटओवर ब्रिज में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने का फैसला लिया है।

नई दिल्ली। मथुरा रोड पर प्रगति मैदान के आसपास सड़क पार करने वालों को जल्द राहत मिल सकेगी। इस क्षेत्र में दो फुटओवर ब्रिज में एस्केलेटर और एक में लिफ्ट चालू होने जा रही है। इससे लोगों को सड़क पार करने में काफी राहत मिल सकेगी।

अभी सीधे सड़क पार करते हैं लोग

कुछ साल पहले दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि चढ़ने के कारण लगने वाले समय और थकावट हो जाने से बहुत से लोग फुटओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ते हैं और सीधे सड़क पार करते हैं।

तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरने पर कई बार उनके जीवन को खतरा हो जाता है तो ऐसा किए जाने से वाहनों के ब्रेक भी लगते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी फुटओवर ब्रिज में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाए जाने का फैसला लिया है।

तीन फुटओवर ब्रिज में लगेंगी लिफ्ट

इसी क्रम में मथुरा रोड पर नए बने तीन फुटओवर ब्रिज में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत काका नगर व प्रगति मैदान के गेट नंबर छह के पास नए बने फुटओवर ब्रिज में एस्केलेटर लगाए जाने का काम छह महीने पहले शुरू किया गया था। काम चल ही रहा था कि इसी बीच चोर इन दोनों फुटओवर ब्रिज से उस पैनल को ही चोरी कर ले गए, जिससे एस्केलेटर चलाया जाना था।

पीडब्ल्यूडी ने बताया कि इस योजना पर काम कर रही जॉनसन कंपनी ने पैनल फिर से मंगा लिए हैं और काम शुरू कर दिया गया है। दोनों फुटओवर ब्रिज के एस्केलेटर एक से डेढ़ माह में शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर नए बने फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट भी जल्द शुरू कर दी जाएगी।

मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, NPS, OPS नहीं अब होगी यूपीएस

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा

नई दिल्ली। हाल के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू करने को मुद्दा बनाने के दांव का केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया है जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा।

कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित राशि

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्यूटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

पुरानी पेंशन स्कीम से कितना है अलग?

एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर ही 10 प्रतिशत योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14 फीसद से बढ़ा कर 18.5 फीसद कर दिया गया है। जो साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा।

ओपीएस के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस।

पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये सुनिश्चित।

ग्रेच्यूटी के अलावा छह माह का वेतन भी एकमुश्त सेवानिवृत्ति पर मिलेगा।

कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ा कर 18 फीसद किया।

पहले वर्ष में सरकार पर 6250 करोड़ रुपये का बोझ।

एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प।

राज्य केंद्र सरकार के माडल को कर सकते हैं स्वीकार।

केंद्र पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023